

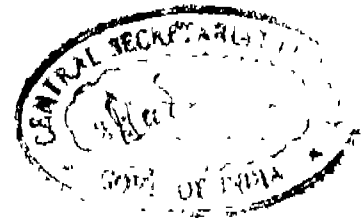


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 132]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 1996/श्रावण 1, 1918

No. 132]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 1996/SHRAVANA 1, 1918

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1996

सं. एफ. 15(30)-बी(डी)/96.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

बजट 1996-97

वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम का भाषण

22 जुलाई, 1996

भाग—'क'

महोदय,

मैं वर्ष 1996-97 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ।

2. असामान्य रूप से शान्तिपूर्ण आम चुनाव ने असामान्य रूप से एक मिश्रित शासनादेश दिया है। इस शासनादेश के प्रति निष्ठावान होना ही प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्त्तव्य था। तदनुसार, विभिन्न स्वरूपों एवं भिन्न-भिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों ने मिलकर इस सरकार को बनाया है। उनमें से अधिकतर दल क्षेत्रीय दल हैं हालांकि उनका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। भारत के धर्मनिरपेक्ष विरासत को बनाए रखने और अपेक्षाकृत तीव्र आर्थिक संवृद्धि और त्वरित सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध प्रतिनिधिमूलक सरकार देने के संकल्प ने ही हमें एकजुट किया है।

3. संयुक्त मोर्चा एक मिला-जुला संघ है। कार्यभार संभालने के पहले, इस मिले-जुले संघ के साक्षीदारों ने "प्रमुख नीतिगत विषयों और एक न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति साझा दृष्टिकोण" नामक एक दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया जिसे सामान्यतया "साझा न्यूनतम कार्यक्रम" कहा जाता है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को हमारे प्रधानमंत्री, श्री देव गोड़ा ने 4 जून, 1996 को राष्ट्र के नाम जारी किया। जब मैंने इस "साझा न्यूनतम कार्यक्रम" पर काम शुरू किया तब मैं मंत्री भी नहीं था। जब हमने अपना यह काम पूरा कर लिया तब मैंने स्वयं को वित्त मंत्री के पद

पर पाया। इसलिए "साम्ना न्यूनतम कार्यक्रम" के प्रति मेरी वचनबद्धता इस पद से भी कहीं अधिक है। माननीय सदस्यों को इस अपराह्न बेला में मेरी वचनबद्धता को परखने के बहुत से अवसर मिलेंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि "साम्ना न्यूनतम कार्यक्रम" ने इस बजट को मूल आधार प्रदान किया है तथा इसकी कार्यसूची का निर्धारण किया है।

4. अद्यतन आर्थिक समीक्षा, 1995-96 को, गत शुक्रवार को सदन के पटल पर रखा गया था। यह 21 पृष्ठों से अनधिक का एक छोटा-सा दस्तावेज है और मुझे आशा है कि यह सप्ताहान्त के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री का काम करेगा। हमारा यह निष्कर्ष है कि आर्थिक संकेतक उच्च संवृद्धि को दर्शाते हैं लेकिन कमजोरी के महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं। अद्यतन आर्थिक समीक्षा ने इन क्षेत्रों की शिनाख्त राजकोषीय घाटे, धीमी कृषि संवृद्धि, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उच्च व्याज दरों और व्यापार घाटे के रूप में की है। सबसे अधिक चिंता की बात वर्ष 1995-96 में कृषि फसल उत्पादन की वृद्धि में 0.9 प्रतिशत तक गिरावट आना है। इन अद्यतन समीक्षा ने राजकोषीय चुनौतियों, आधारभूत संरचना की चुनौतियों और रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन को भी मुख्य मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिनपर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. साम्ना न्यूनतम कार्यक्रम ने घोषणा की है कि सरकार उन आर्थिक नीतियों का अनुसरण करेगी जो सामाजिक न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देगी तथा अधिक आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर करेगी। हमारे लिए न तो रोजगारविहीन विकास का और न ही उस विकास का कोई उपयोग है जिससे हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अछूता रहता है। हम कृषि और उद्योग पर से नियंत्रण और विनियम हटा देंगे। हम अधिक विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त और प्रतिस्पर्धी बनाए रखेंगे। हम अपनी कर प्रणाली में सुधार करेंगे। हम भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) जैसे स्वतंत्र विनियामकों को मजबूत बनाते हुए भी विस्तीय और पूंजी बाजारों के सुधार को विस्तृत और गहन बनाएंगे। इससे भी अधिक, हम राजकोषीय और मौद्रिक विवेक, जो निम्न मुद्रास्फीति और तीव्र विकास की कुंजी है, का अनुपालन करेंगे।

6. इसलिए इस बजट के सात मुख्य उद्देश्य हैं :

- आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के पथ पर निरन्तर अग्रसर होना जिसका लक्ष्य आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाना है।
- गरीबों की चिन्ताओं पर ध्यान देना तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से न्यूनतम बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- अधिक रोजगार की उपलब्धि के लिए कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में विकास को सुनिश्चित करना तथा विस्तृत आधार प्रदान करना।
- राजकोषीय दूरदर्शिता तथा वृहत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
- विशेषकर आधारभूत क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना।
- मानव विकास का संवर्धन करने के लिए प्रमुख मध्यवर्तियों को सुदृढ़ बनाना।
- अच्छे निर्यात निष्पादन और अधिक विदेशी निवेश प्रवाहों के जरिए भुगतान संतुलन को व्यवहार्य बनाना।

अब मैं अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करूँगा तथा अपने नीति संबंधी उपायों के बारे में बताऊँगा ताकि उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके जिन्हें मैंने अभी-अभी निर्दिष्ट किया है।

कृषि और ग्रामीण ऋण :

7. साझा न्यूनतम कार्यक्रम व्यापक आधार वाले कृषि विकास पर बल देता है और इसका उद्देश्य कृषि तथा कृषि-उद्योगों विशेषकर लघु और सीमान्त कृषकों को मिलने वाले ऋण के प्रवाह को पाँच वर्षों के अन्दर दुगुना करना है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कई घटकों वाली एक एकीकृत योजना तैयार की है।

8. प्रथम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की शेयर पूँजी 500 करोड़ रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर अगले पाँच वर्षों में 2000 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। चालू वर्ष में नाबाई की प्रदत्त शेयर पूँजी दुगुना करके 1000 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है। भारत सरकार के हिस्से के लिए 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है और शेष 400 करोड़ रुपए का अंशदान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

9. दूसरे, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आई.आई.डी.एफ) में, जिसका संचालन नाबाई द्वारा किया जाता है और जिसका वित्तपोषण उधार देने के लक्ष्यों की अपनी प्राथमिकता को पूरा न कर पाने वाले वाणिज्यिक बैंकों के अंशदान से किया जाता है, पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण आधारभूत विकास निधि राज्य सरकारों को मध्यम एवं लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण तथा जल-संभर प्रबंध जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करता है। 1995-96 के दौरान, नाबाई ने 2,489 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 19 राज्यों को कुल 1984 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। चालू वित्त वर्ष के दौरान, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए 2,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

10. ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अतिरिक्त, मैं एक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का प्रस्ताव कर रहा हूँ जिसके अन्तर्गत केन्द्र समतुल्य आधार पर चुनीदा बड़ी सिंचाई और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को ऋणों के तौर पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मैं इस योजना को शुरू करने के लिए 1996-97 में 800 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ जिसे उन सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है जहाँ परियोजना लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो और जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हो। मैं चालू वित्त वर्ष में उन सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 100 करोड़ रुपए आवंटित कर रहा हूँ जहाँ मात्र थोड़े ही अतिरिक्त संसाधनों से परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता हो और किसानों को सुनिश्चित जलापूर्ति का लाभ मिल सकता हो। इन योजनाओं के जरिए 100,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा और मुझे यह आश्वासन दिया गया है कि इन भूमियों पर अगले चार कृषि मौसमों में से एक मौसम के दौरान

ही पहली फसल काटी जाएगी। बड़ी परियोजनाओं और 100,000 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का छीरा योजना आयोग द्वारा अगले कुछ दिनों में घोषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम पर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

11. चौथे, वाणिज्यिक या उच्च प्रौद्योगिकी कृषि तथा बागवानी, पुष्प कृषि तथा कृषि-संसाधन जैसी संबद्ध गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्त संस्थाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। नाबार्ड उसका मुख्य प्रवर्तक होगा। राष्ट्रीय स्तर की अन्य वित्तीय संस्थाओं और संबंधित राज्य सरकारों से इकिविटी में भागीदारी करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

12. पाँचवे, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ यह सहमति हो गई है कि दो या तीन निकटस्थ जिलों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले नए निजी स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्थानीय संस्थाएँ ग्रामीण बचतों को जुटा सकेंगी और इसके साथ ही उन्हें स्थानीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध करा सकेंगी।

13. अंततः हमने अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। दो सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री ने फॉस्फेटी और पोटैशी उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। सरकार ने एकीकृत अनाज विकास - चावल कार्यक्रम के अंतर्गत पावर टिलरों को 30,000 रुपए अथवा प्रत्येक पावर टिलर की लागत के 50 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। छोटे ट्रैक्टरों के संबंध में प्रति ट्रैक्टर 30,000 रुपए की दर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता संबंधी स्कीम अभी केवल छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित है। मैं यह स्कीम सभी किसानों के लिए लागू कर रहा हूँ। मैं छिड़काव-यंत्रों और ड्रिप सिंचाई संबंधी आर्थिक सहायता की दर को उस प्रणाली की लागत के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर रहा हूँ और उसकी उच्चतम सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह सीमा बढ़ाकर प्रणाली की लागत के 90 प्रतिशत तक की जा रही है।

बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ

14. बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाना प्रधानमंत्री श्री देव गोड़ा का सर्वप्रथम कार्य था। इससे राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाने के संयुक्त मोर्चे के संकल्प का पता चलता है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने वर्ष 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले सात उद्देश्यों को स्वीकार करने की सिफारिश की। ये उद्देश्य हैं : सुरक्षित पेयजल की शत-प्रतिशत व्यवस्था; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शत-प्रतिशत उपलब्धता, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना; सभी निराश्रित गरीब परिवारों को सरकारी आवास सहायता; मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार; सभी गाँवों और बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ना;

और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना।

15. इन उद्देश्यों को अब केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों और राज्य आयोजनाओं की स्कीमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि मैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए 2466 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा हूँ ताकि इन स्कीमों के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध हो सके। हमारा इरादा है कि इस राशि में से गंदी-बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आश्रय-स्थल तथा अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सके। सात स्कीमों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच इस बढ़ी हुई आवंटन राशि का निर्धारण उनके साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा किया जाएगा।

आधारभूत वित्त-व्यवस्था

16. अद्यतन आर्थिक समीक्षा में आधारभूत मोर्चे पर मिलने वाली व्यापक चुनौती पर प्रकाश डाला गया है। हमारी आधारभूत संरचना-विशेषकर विद्युत और सड़कों की स्थिति बड़ी शोचनीय है। हम उस समय तक 7 प्रतिशत की संवृद्धि कायम नहीं रख सकते हैं जब तक कि हम इन आधारभूत क्षेत्रों को पुनः सुदृढ़ न बना लें। दूर-संचार, रेलवे तथा पत्तनों के लिए भी बहुत अधिक निधियों की जरूरत है।

17. आधारभूत संरचना के लिए दीर्घावधिक वित्त, विशेष रूप से 15-20 वर्षीय वित्तीय साधनों, की आवश्यकता होती है जोकि अब तक भारतीय बाजार में भी स्वीकार्य नहीं है। अतः मैं एक आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी (आई.डी.एफ.सी) की स्थापना का प्रस्ताव कर रहा हूँ। इस कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी सहित सम्मिलित किया जाएगा। केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक बैंक और वित्तीय संस्थाएँ शेयर पूंजी में अंशदान करेंगे। मैं केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान कर रहा हूँ। शेयर पूंजी में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभिक अंशदान भी 500 करोड़ रुपये का होगा। अन्य बातों के साथ-साथ आई.डी.एफ.सी. एक प्रत्यक्ष ऋणदाता, पुनः वित्तपोषण संस्था और वित्तीय गारंटीदाता के रूप में भी कार्य करेगा। मुझे विश्वास है कि आई.डी.एफ.सी. निम्नतम संभव बाजार दरों पर दीर्घावधिक निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों निवेशकों को प्रेरित करेगा।

18. मैं आधारभूत संरचना संबंधी निवेश के लिए कुछ कर प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी कर रहा हूँ, जिनकी रूपरेखा मैं बाद में प्रस्तुत करूँगा।

19. माननीय सदस्यगणों को जानकारी है कि केन्द्र सरकार पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कर चुकी है। हमें बहुत शीघ्र ही एक विश्व-स्तर की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की आवश्यकता है। मैंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने का निर्णय किया है। प्राधिकरण

अब भारत के भीतर और विदेशों दोनों से राजमार्ग विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

लघु उद्योग

20. उद्यमी-चालित लघु क्षेत्र हमारे उद्योग का मेरुदण्ड है। मैं इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्णरूपेण वचनबद्ध हूँ। निम्नलिखित कुछ उपाय तत्काल शुरू किए जाएंगे।

- * पहला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास उसकी प्रौद्योगिक विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना में लगभग 175 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त संचित निधि है। मैं अब यह प्रस्ताव कर रहा हूँ कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 50 लाख रुपये तक की आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए राज्य वित्त निगमों (एस.एफ.सी) और वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्वित्तपोषण करना चाहिए। यह राज्य वित्त निगमों और बैंकों से आधुनिकीकरण निधियाँ मांगने वाली लघु इकाइयों के लाभ के लिए निर्णय करने के कार्य को विकेन्द्रीकृत करेगा।
- * दूसरा, 50 लाख रुपये तक के मिले-जुले ऋणों के लिए राज्य वित्त निगमों आदि की एक ही स्थान पर उपलब्धि की स्कीम (सिंगल विन्डो स्कीम) के लिए अब पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। मैं इस उच्चतम सीमा को दुगुना करके 100 लाख रुपये कर रहा हूँ।
- * तीसरा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं तथा साथ ही निजी कंपनियों द्वारा स्थापित उद्यम पूंजी निधियों में निधि की कुल संचित राशि को 50 प्रतिशत तक की राशि की भागीदारी करेगा बशर्ते की ऐसी निधि लघु उद्योगों के वित्तपोषण हेतु समर्पित हो।
- * चौथा, बड़ी संख्या में लघु इकाइयों को आई.एस.ओ. 9000 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, ऋणदाता संस्थाओं को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की ऋण देने की प्रत्यक्ष स्कीम के समान शर्तों पर अंतिम उधारकर्ताओं को ऋण देने के योग्य बनाया जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उन ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

21. विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक प्रगति और समृद्धि की कुंजी है। भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने, विशेषकर कृषि, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हमारी आधारभूत संरचना में व्यापक नवीकरण की आवश्यकता है।

22. मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त मैचिंग अनुदान प्रदान कर रहा हूँ। मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आगामी दो वर्षों में वृद्धिकारी रूप में अर्जित किए जाने वाले प्रत्येक वाणिज्यिक रुपए को बजट के दूसरे रुपए से प्रतिसंतुलित करूंगा।

23. मैं प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि, जिसका सृजन देशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक अनुप्रयोग के चरण तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए वर्ष 1994-95 में किया गया था, को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। अन्तरिम बजट में इसे 10 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति इस सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए मैं तत्काल 30 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रहा हूँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीघ्र ही प्रौद्योगिक विकास बोर्ड की स्थापना की घोषणा करेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

24. सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया है कि मूल्य स्थिरता तथा गरीबों को अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है जहाँ इसकी अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है, वहीं से इसकी शुरुआत करनी है। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं और उचित समय पर उनकी घोषणा कर दी जाएगी।

वेतन आयोग

25. पांचवें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1996 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। अनुमानित व्यय की पूर्ति के लिए इस बजट तथा साथ ही रेलवे बजट में निधियों का प्रावधान किया गया। इस बीच मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि अंतरिम राहत की एक और किस्त देने के प्रश्न को संतोषजनक ढंग से हल कर लिया गया है।

अन्य कल्याणकारी उपाय

26. प्रधानमंत्री जी ने बार-बार घोषणा की है कि यह सरकार गरीबों की सरकार है तथा गरीबों के लिए है। सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि इस सरकार का आदर्श-वाक्य होगा। जब तक देश का सकल घरेलू उत्पाद अगले 10 वर्षों में बढ़कर प्रति वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता, तब तक हम देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकेंगे। तथापि, असुरक्षित वर्ग के लोगों का पता लगाने तथा उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ लक्ष्य समूहों का पता लगाया है जिनकी सहायता करने की जरूरत है और मैं इनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए कतिपय नए उपायों का प्रस्ताव कर रहा हूँ। इन उपायों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के जरिए तथा यथासंभव गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से किया जाएगा।

- * प्रारम्भिक रूप से मैं वृद्धावस्था गृहों की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि अलग से निर्धारित कर रहा हूँ तथा निर्धन बच्चों, वे चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, के लिए आवासीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान कर रहा हूँ। हमारा इरादा है कि ये दोनों कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इन कार्यक्रमों को संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जाएगा।

- * जिन राज्यों के पास महिला विकास निगम हैं या जो महिला विकास निगम स्थापित करेंगे उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में निराश्रित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र या स्कीमें चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अलग रखी गई है।
- * मैं 5 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक सामूहिक निधि से एक राष्ट्रीय रूग्णता सहायता निधि स्थापित कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त, राज्य रूग्णता सहायता निधि, जिसे स्थापित करने के लिए हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेंगे, की सामूहिक निधि में अंशदान के लिए 25 करोड़ रुपए अलग रखा गया है। इन निधियों को दिए गए दान की शत-प्रतिशत राशि आयकर से मुक्त होगी। इन निधियों का इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के लिए शल्य/चिकित्सा या उपचार हेतु बहुत गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- * जिन लारी या बस चालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनके परिवारों को प्रति परिवार 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसे राज्य सरकारों द्वारा भी प्रतिपूर्ति आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।
- * हमारे जो हमाल भाई दिन-रात मेहनत करते हैं उनके आश्रय के लिए आवासीय सुविधाओं के निर्माण हेतु मैं 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूँ, यह योजना भी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

27. सरकार उन राज्यों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना तैयार करने पर विचार करेगी, जो छोटे-छोटे वन उत्पादों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा वनों में काम करने वाले अन्य कमजोर वर्गों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं।

राजकोषीय अनुशासन

28. हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय चुनौती है। संयुक्त मोर्चा सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से भी नीचे लाने के लिए वचनबद्ध है। यही साक्षात् न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है और मेरा भी आने वाली समयावधि में यही करने का इरादा है। निस्संदेह, इस नीति का एक भाग अधिक राजस्व जुटाना है। परंतु एक विश्वसनीय सरकारी व्यय प्रबंध नीति के बिना, राजकोषीय घाटे में कमी करने का कोई कार्यक्रम अविच्छिन्न नहीं रखा जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि कोई भी ऐसी आडम्बरहीनता अथवा क्षमता के विरुद्ध नहीं है। जब भी मैं अपनी बातों अथवा कार्यों के लिए किसी आलोचना का सामना करता हूँ तो मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनता हूँ। वह आवाज मुझे कहती है कि मुझे उन लोगों, जिन्हें सचमुच भय है कि वे व्यर्थ ही प्रभावित होंगे, के लिए अधिक समझ और सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। मैं इस स्थिति को भी स्वीकार करता हूँ कि एक सुदृढ़ व्यय प्रबंध मात्र तकनीकी

कार्य नहीं है परंतु इसमें समानता, न्यायसंगतता और भेदभाव नहीं करने के मुद्दे भी शामिल हैं। इस संबंध में एक उचित नीति तैयार करने के लिए मेरा एक उच्च-स्तरीय व्यय प्रबंध और सुधार आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें विशिष्ट राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री और प्रशासक सम्मिलित होंगे। इस आयोग को, जहाँ तक केन्द्र सरकार का संबंध है, सरकारी व्यय प्रबंध और नियंत्रण पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा और मुझे आशा है कि इसे इससे अधिक समय नहीं देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को तत्काल सर्वसाधारण की जानकारी में ला दिया जाएगा ताकि हम एक ऐसे मुद्दे, जिसका हमारे आर्थिक भविष्य पर महत्वपूर्ण असर होगा, पर एक संसूचित सार्वजनिक बहस करा सकें।

29. मैं आर्थिक सहायता पर एक चार्ज-पत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस दस्तावेज में दृश्य और छिपी हुई सभी आर्थिक सहायताओं की सूची रहेगी ताकि सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में आर्थिक सहायताओं के समग्र स्तर और उनके उपयुक्त लक्ष्य-निर्धारण पर एक संसूचित बहस और सर्वसम्मति हो सके।

30. इस बीच, मेरा इरादा नकदी प्रबंध, बजटीय उच्चतम सीमा के अनुपालन, पोर्टफोलियो समीक्षा और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से अधिप्राप्ति की पर्याप्तता से संबंधित मामलों पर दृढ़ रहने का है।

31. माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि सितम्बर, 1994 में तदर्थ राजकोषीय हंडियों की प्रणाली को वर्ष 1997-98 तक समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। पिछले वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक के अनुभवों ने एक वर्ष की सीमा के भीतर से कम अवधि पर रुकने की कठिनाई दर्शाई है। फिर भी, मैं आश्वस्त हूँ कि तदर्थ राजकोषीय, हंडियों की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा होने से पूर्व हमें एक बेहतर व्यय नियंत्रण कार्यविधि तैयार करने की आवश्यकता है। हमें मुद्राकरण के सभी रूपों सहित सही बजटीय घाटा सूचित और परिभाषित करने की एक अधिक पारदर्शी विधि की भी आवश्यकता है। मैं आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय इस संबंध में ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करूँगा ताकि मौद्रिक नीति बनाते और कार्यान्वित करते समय भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक स्वायत्तता मिल सके।

बीमा, बैंकिंग और पूँजी बाजार

32. इसके पूर्व मैंने दीर्घावधिक वित्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बीमा का संदर्भ दिया था। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम बीमा क्षेत्र में हमारी दो प्रमुख संस्थाएँ हैं। मैं इन्हें सुदृढ़ करने का इरादा रखता हूँ। बीमाकर्ता की सुदृढ़ता को उसकी सेवा और उत्पादों की सीमा और गुणवत्ता तथा उन सेवाओं और उत्पादों का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या द्वारा मापा जाता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं मध्यम वर्ग और निर्धनों के लिए लक्षित दो नई सेवाएँ प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को प्रेरित कर पाया हूँ।

33. जीवन बीमा निगम 'जीवन सुरक्षा' नामक एक नई पेंशन योजना प्रस्तुत करेगा। इस नई योजना का ब्योरा अलग से घोषित किया जाएगा परंतु यह योजना कैसे कार्य करेगी इसका उदाहरण दिया जा सकता है। एक व्यक्ति, जो इस योजना में 30 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह मात्र 250 रुपए का भुगतान करके अभिदान करता है, वह 60 वर्ष की आयु से प्रारंभ करके जीवन भर प्रतिमाह 3500 रुपए की पेंशन प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति पर तत्काल पेंशन के संराशिकृत मूल्य का 25 प्रतिशत अर्थात् लगभग 1 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त करेगा। अगर बीमाकृत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उसके/उसकी पति/पत्नी को जीवन-पर्यन्त पर्याप्त पेंशन अदा की जाएगी। यह योजना काफी अधिक संख्या में लोगों के बीच उनके कार्यकाल की अवधि के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए लम्बे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति करेगी। यह वैयक्तिक-सह-परिवार पेंशन योजना शुरू करने के लिए मैं कुछ राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जिनकी रुपरेखा में बाद में दूंगा।

34. चिकित्सा बीमा एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ सेवा की गुणवत्ता को अत्यधिक सुधारा जा सकता है। मौजूदा मेडिकेयर योजना के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम कवच 83,000 रुपए है, जिसे आगे विभिन्न संघटकों में खण्डित किया गया है। इस उच्चतम सीमा को एकल कुल सीमा सहित बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा रहा है।

35. इसके अतिरिक्त, साधारण बीमा निगम हमारे अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त एक नई निम्न मूल्य वाली मेडिकेयर पॉलिसी शुरू करेगा। जीवन जीवन बीमा निगम के लिए ब्रान्ड नाम है और हम बौद्धिक संपत्ति अधिकार का सम्मान करते हैं। इसलिए हम इस नई योजना को "जन-आरोग्य" नाम दे रहे हैं। यह पॉलिसी केवल 70 रुपए की वार्षिक प्रीमियम सहित प्रतिवर्ष 5,000 रुपए तक का कवच प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, पति, पत्नी और 25 वर्ष से कम आयु वाले दो बच्चों सहित चार व्यक्तियों का परिवार 240 रुपए का वार्षिक प्रीमियम अदा कर सकता है और पूरे परिवार के लिए 20,000 रुपए का कवच प्राप्त कर सकता है। साधारण बीमा निगम इस योजना के ब्योरे शीघ्र घोषित करेगा।

36. मैंने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को अपने कारोबार में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। मैंने जीवन बीमा निगम को अद्यतन मृत्यु-दर सारणी के आधार पर प्रीमियम ढाँचे की समीक्षा करने का भी निदेश दिया है।

37. जनवरी, 1996 में एक अंतरिम असांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मैं अब इसे एक सांविधिक निकाय बनाने और उचित रूप से शक्ति प्रदान के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ। जब मैं अगले बजट में बीमा के विषय पर आऊंगा, मैं बीमा उद्योग की पुनर्संरचना के लिए किये जाने वाले उपायों के क्रम सहित साक्षात् न्यूनतम कार्यक्रम में रुपायित कुछ पॉलिसी पैरामीटरों पर चर्चा करूंगा।

38. बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजारों का सुधार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता में सुधार दर्शाया है तथा वे उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश ने प्रतिस्पर्धा का स्वागत योग्य उपाय शामिल किया है। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी बैंकों को पुनःपूँजी प्रदान करने के लिए सरकार ने कुल 11,840 करोड़ रुपए दिए हैं। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इन बैंकों में से तीन बैंक अब उस पूँजी का कुछ हिस्सा, जो 747 करोड़ रुपए बैठता है, वापस करने की स्थिति में हैं, जो उनके कार्य-निष्पादन में सुधार को दर्शाता है। संसाधनों के इस पुनः प्रवाह से अन्य कुछ सरकारी बैंकों को पुनः पूँजी प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जिसके लिए 1996-97 में 909 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के कुछ मजबूत बैंक अपने तौर पर पूँजी बाजार से सीधे ही अपने लिए पुनः पूँजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय स्टेट बैंक आज के पूँजी बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रतिभूति-पत्र (स्क्रिप) माना जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और उन्हें पुनः पूँजी प्रदान करने के लिए मैं 1996-97 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर रहा हूँ।

39. नए निवेश के लिए धन एकत्रित करने में पूँजी बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि प्रभावशाली विनियमन, अधिक पारदर्शिता और बेहतर व्यापारिक तथा निपटान प्रणालियों के माध्यम से पूँजी बाजारों का अच्छा विकास हो। हमारे मुख्य स्टॉक एक्सचेंजों ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की शुरुआत कर दी है। केन्द्रीय निक्षेपागार, जिसके इस वर्ष आरंभ हो जाने की संभावना है, पूँजी बाजारों के आधुनिकीकरण की ओर एक और ऐतिहासिक कदम होगा।

40. विदेशी संस्थात्मक निवेशकों को मार्गनिर्देशित करने वाले मौजूदा विनियम केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देते हैं। एकल विदेशी संस्थात्मक निवेशक के मामले में 5 प्रतिशत तक की तथा किसी सूचीबद्ध कंपनी के स्टॉक में सभी विदेशी संस्थात्मक निवेशकों के लिए कुल 24 प्रतिशत की एक सीमा है। यह प्रतिवेदन किया गया है कि इन सीमाओं को उदारीकृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विदेशी संस्थात्मक निवेशक आधारभूत संरचनाओं में निवेश नहीं कर सकते क्योंकि आधारभूत परियोजनाएँ नई कंपनियों द्वारा स्थापित की जाती हैं, जिन्हें कुछ समय तक सूचीबद्ध करने की संभावना नहीं होती। इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि यह सीमा सकल विदेशी संस्थात्मक निवेशक के मामले में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाए, तथापि, सभी विदेशी संस्थात्मक निवेशकों के मामले में यह कुल सीमा 24 प्रतिशत ही रहेगी। मैं उन्हें असूचीबद्ध कंपनियों में भी इसी प्रकार से निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ जिस प्रकार से उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। 'सेबी' द्वारा पृथक रूप से संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

गैर-बैंकिंग वित्त संस्थाएं

41. निगमित और गैर-निगमित कई गैर-बैंकिंग वित्त संस्थाओं के कार्यकलापों के संबंध में समय-समय पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। मैं सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्न हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक से विचार-विमर्श करके हमने सभी प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियामक शक्तियों को और मजबूत करने के लिए इस सदन के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करने का निर्णय किया है।

निगमित क्षेत्र

42. यह व्यापक रूप से माना जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 को विस्तृत रूप से पुनः लिखने की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ कार्य पहले ही किया जा चुका है। मेरा इरादा एक नया प्रारूप बनाने और उसे सर्वसाधारण में चर्चा के लिए तैयार करने हेतु विधि, अर्थशास्त्र और कंपनी कार्य की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों का एक छोटा प्रारूपण दल गठित करना है। मेरी अंतिम निर्धारित तारीख पहली जनवरी, 1997 है।

43. इस बीच, मैं निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए मौजूदा अधिनियम में कुछ अत्यावश्यक संशोधन लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ :

- * जमाराशियों के मूलधन की वापसी-अदायगी अथवा ब्याज के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को इन श्रुतियों को दूर करने तक और अधिक जमाराशियाँ जुटाने से बहिष्कृत किया जाएगा।
- * किसी कंपनी को बंद करने के मामले में उसके कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन की बकाया राशि संबंधी दावों के बारे में 1000/- रुपये की वर्तमान सीमा असंगत रूप से बहुत कम है। इस सीमा को बढ़ाया जाएगा।
- * म्युचुअल फंड और उद्यम संबंधी पूंजी फंड को कंपनियों में उनकी धारिताओं के संबंध में मत देने की अनुमति दी जाएगी।
- * बिना मत वाले शेयरों को जारी की गई इक्विटी पूंजी के 25 प्रतिशत तक होने की अनुमति दी जाएगी। इससे पूंजी क्षेत्र में एक समान स्तर लाने संबंधी भाग को पूरा करने में दूरगामी सहायता मिलेगी।
- * आधारभूत क्षेत्र की कंपनियों को उन शेयरों को जारी करने की अनुमति दी जाएगी जो उनके जारी होने की तारीख से 20 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रतिदेय हो जाते हैं।

44. माननीय सदस्य मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि ये परिवर्तन अनिवार्य हैं तथा इन्हें तत्काल लागू किया जाना चाहिए। अगले वर्ष, मैं सदन में एक नया कंपनी विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

45 प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए, भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी तक सरल अभिगम्यता प्रदान की जानी चाहिए। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक प्रौद्योगिकी संबंधी आयातों

के लिए स्वतः ही अनुमोदन प्रदान करता है बशर्ते कि रॉयल्टी घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत तथा निर्यात संबंधी बिक्री पर 8 प्रतिशत तक सीमित रखी जाए और एकमुश्त भुगतान 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा मामला-दर-मामला अनुमोदन दिए जाने की अपेक्षा होती है। उद्योगों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि स्वतः अनुमोदन के लिए 1 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस मांग के प्रत्युत्तर में यह निर्णय लिया गया है कि इस सीमा को बढ़ाकर 2 मिलियन डॉलर (लगभग 7 करोड़ रुपये के बराबर) कर दिया जाए। इस उदारीकरण से प्रौद्योगिकी आयात संबंधी बहुसंख्यक मामलों को सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा।

46. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना एक प्रमुख ऋण और पुनर्निर्माण अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। तेजी से होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप, पुनर्निर्माण कार्य संबंधी भार को विभिन्न श्रेयगृहधारकों, जिनमें विकासात्मक वित्तीय संस्थान तथा बैंक भी शामिल हैं, द्वारा मिलजुल कर बांटा जा रहा है। इसलिए, मैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को एक पूर्णतया सर्व-उद्देशीय विकास वित्त संस्था के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखता हूँ, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा। मैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को शासित करने वाले अधिनियम में शीघ्र ही आवश्यक परिवर्तन प्रस्तुत करूँगा।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, टैरिफ आयोग तथा विनिवेश आयोग

47. साक्षा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वायदों के अनुसार, सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया है। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन भी शीघ्र ही किया जाएगा। ये दोनों संस्थाएँ मिलकर प्रति वर्ष कम से कम 10 बिलियन डॉलर की पूंजी आकर्षित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अत्यधिक बढ़ावा देंगी तथा उनका अनुमोदन करेंगी।

48. विदेशी निवेश संबंधी अनुमोदनों के शीघ्र निपटान तथा इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 35 उद्योगों की सूची का विस्तार करने का निर्णय किया है, जो 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन के लिए पात्र हैं। इस विस्तृत सूची की घोषणा मेरे सहयोगी, उद्योग मंत्री द्वारा अलग से की जाएगी। इस समय स्वतः अनुमोदन प्रक्रिया इस अपेक्षा के अधीन है कि विदेशी इक्विटी के मूल्य में पूंजीगत वस्तुओं का कुल आयात भी शामिल होना चाहिए। यह शर्त वर्ष 1991 में आरंभ की गई थी जब पूंजीगत वस्तुओं का आयात, आयात लाइसेंसिकरण प्रणाली के अधीन था। चूंकि वर्ष 1992 से पूंजीगत वस्तुओं पर से आयात लाइसेंसिकरण संबंधी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं इसलिए इस शर्त को भी समाप्त किया जा रहा है।

49. सरकार ने एक स्वतंत्र टैरिफ आयोग की स्थापना के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

50. सरकार ने विनिवेश आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। विनिवेश करने संबंधी कोई भी निर्णय सुस्पष्ट तौर पर लिया एवं कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे विनिवेश से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन करने तथा सरकारी उद्यमों को मजबूत करने हेतु निधि सृजित करने के लिए किया जाएगा। 1996-97 के अंतरिम बजट में विनिवेश के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था। मैं उतनी ही राशि का ऋण लेने का प्रस्ताव करता हूँ। विनिवेश संबंधी यह कार्य तीन किस्तों, संभवतः सितम्बर, नवम्बर तथा जनवरी/फरवरी में किया जाएगा।

औद्योगिक रूग्णता

51. रूग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम (एस.आई.सी.ए.) में रूग्णता की परिभाषा बहुत संकुचित है तथा इससे आरम्भिक अथवा सम्भावित रूग्णता का पता नहीं चलता। प्रबंधकगण अपनी वैध जिम्मेवारियों को निपटाने में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम का प्रयोग करते रहे हैं। वर्तमान प्रबंध प्रणाली में, कामगार, वित्तीय संस्थान, बैंक तथा सरकार अक्सर घाटे में रहते हैं। मैंने रूग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्य प्रणाली का पूर्ण पुनरीक्षण आरम्भ किया है तथा संसद के शीतकालीन अधिवेशन में मेरा एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है।

केन्द्र-राज्य संबंध

52. बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संबंध में मुख्य मंत्री सम्मेलन का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। केन्द्र-राज्य संबंधों तथा संघवाद के राजनीतिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री का मुख्य मंत्रियों का एक और सम्मेलन बुलाने का इरादा है। पिछले सम्मेलन में, मुख्य मंत्रियों ने विचार प्रकट किया था कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित बहुत सी स्कीमों को उसी प्रकार जारी रखा जाए तथा उनका वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाता रहे। यद्यपि, हम मुख्य मंत्रियों के विचारों का आदर करते हैं, फिर भी हमारी इच्छा है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित, अधिकांश स्कीमों को राज्य सरकारों के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस बीच, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को और अधिक छूट दी जाएगी। अन्य सभी स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का एकीकरण किया जाएगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए बुनियादी हकदारी अनुपात तैयार किया जाएगा। राज्य अपनी वार्षिक हकदारी के भीतर ऐसी स्कीमों को क्रियान्वयन हेतु चुनने के लिए स्वतन्त्र होगा जो उनकी आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप हों। योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श करके संशोधित मार्गनिर्देशों तथा कार्य पद्धतियों को तैयार कर रहा है।

53. दसवें वित्त आयोग की इस सिफारिश के बारे में कि करों का एक एकल विभाज्य पूल बनाया जाए जिससे सभी करों को केन्द्र और राज्यों में बांटा जा सके, मैं माननीय सदस्यों के बीच एक चर्चा-पत्र परिचालित करना चाहता हूँ। पहली दृष्टि में, वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रीय हित में प्रतीत होती है लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले इस विषय पर बहस कर ली जाए।

54. साक्षा न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किया गया है कि सरकार छः महीने के भीतर एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें नौवीं योजना की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाएगी। यद्यपि, इस बजट में बहुत से कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि चार महीने के भीतर ही नौवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में एक दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) तैयार किया जाए। नौवीं योजना के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा जाएगा तथा संसाधन जुटाने और व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसमें जिम्मेवारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए स्पष्ट नीतियों का उल्लेख किया जाएगा। इस वर्ष आरम्भ किए गए उपायों के पश्चात् अब एक अधिक विस्तृत सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिसमें निर्धनता उन्मूलन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

55. अब मैं संक्षिप्त रूप से बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

56. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 1995-96 के संशोधित अनुमानों के ब्यौर फरवरी, 1996 में अंतरिम बजट के साथ प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए, मैं इन अनुमानों की फिर से चर्चा नहीं करूंगा। नीचे दिए गए आंकड़े 1996-97 के बजट अनुमान हैं तथा मैं आयोजना व्यय के लिए 1995-96 के बजट अनुमानों के साथ उनकी तुलना करूंगा।

57. 1996-97 के लिए कुल व्यय 204,698 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस राशि में से, 54,685 करोड़ रुपए केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता के रूप में हैं जो कि 48,500 करोड़ रुपए की तुलना में 13 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। आयोजना-भिन्न व्यय की राशि 150,013 करोड़ रुपए रखी गई है।

58. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता को 19,506 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,972 करोड़ रुपए किया जा रहा है। सहायता राशि में यह वृद्धि राज्यों को सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ, को कार्यान्वित करने हेतु निधियां प्रदान करने के कारण होगी।

59. केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता को 28,994 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 32,713 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

60. निर्धनता उन्मूलन संबंधी सभी कार्यक्रमों का उन्हें सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक धनराशि प्रदान करने की दृष्टि से पुनरीक्षण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 1263 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2195 करोड़ रुपए कर दी गई है। ग्रामीण रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन विभाग के लिए आवंटन की राशि 6437 करोड़ रुपए है।

61. उर्वरक विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 205 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 373 करोड़ रुपए कर दी गई है जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

62. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए, गैर-पारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन को 87 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 334 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

63. अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य वित्त मंत्री को इस बात के लिए क्षमा कर देंगे यदि वह निर्यात के प्रति पक्षपात करता है। आखिरकार मुझे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक प्रशिक्षण का अनुभव रहा है। हमारी कार्यसूची में निर्यात संवर्धन का विषय सबसे ऊपर रहेगा। इसलिए, मैं हाल ही में स्थापित "इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड" के लिए 50 करोड़ रुपए की सामूहिक राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं उद्योग और व्यापार क्षेत्र से अपील करता हूँ कि वे इसी वित्तीय वर्ष में कम से कम इतनी ही राशि का योगदान करें। नाजुक संतुलन आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। निर्यात संवर्धन और बाजार विकास हेतु आयोजना-भिन्न प्रावधान की राशि भी 315 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 460 करोड़ रुपए कर दी गई है। मान्य निर्यातकों को अब सीमान्त उत्पाद शुल्क की नकद वापसी राशि शीघ्र ही मिल जाया करेगी।

64. स्वास्थ्य विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 647 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 792 करोड़ रुपए कर दी गई है।

65. शिक्षा विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि में भारी वृद्धि करके इसे 1825 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3388 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

66. यह सरकार सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का विस्तार करके महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिला और बाल विकास विभाग के लिए वार्षिक आयोजना आवंटन को 730 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 847 करोड़ रुपए किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास स्कीम के लिए आवंटन राशि 588 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 682 करोड़ रुपए की जा रही है।

67. श्रम मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन 136 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 188 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कामगारों के कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार और उनके प्रशिक्षण से संबंधित स्कीमों के लिये प्रावधानों में वृद्धि की गई है।

68. कुछ दिन पहले प्रस्तुत किए गए रेल बजट में, सरकार ने चालू वर्ष के लिए रेलवे योजना में 8130 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की है जिसके साथ 1269 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी प्रदान की गई है। आंतरिक संसाधन उपार्जन संबंधी अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रेलवे की योग्यता के आधार पर, वर्ष के दौरान, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए में बजटीय सहायता में वृद्धि करने पर विचार करेगा।

69. भूतल परिवहन मंत्रालय के लिये आयोजना आवंटन की राशि 240 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1322 करोड़ रुपए कर दी गई है जो मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए है। कन्टेनर यातायात के लिए कोची और तूतीकोरिन को महत्वपूर्ण यानांतरण पत्तन बनाने की स्कीमें भी तैयार की जा रही हैं।

70. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप की तरफ से यह निरंतर माँग बनी रही है कि परियोजनाओं के वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन की लागत का निर्धारण करने संबंधी मानदण्डों को लचीला बनाया जाए। उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मैंने इन माँगों को स्वीकार कर लिया है। हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि इन महत्वपूर्ण द्वीपसमूहों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए द्वीप विकास प्राधिकरण को सक्रिय बनाया जाए।

71. माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना को चालू वर्ष में भी जारी रखा जा रहा है। इस स्कीम के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

72 1996-97 के लिए आयोजना-भिन्न व्यय 150,013 करोड़ रुपए रखा गया है जब कि इसकी तुलना में 1995-96 के बजट अनुमानों में यह राशि 123651 करोड़ रुपए तथा 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 134,320 करोड़ रुपए थी। उपरोक्त वृद्धि में, 8000 करोड़ रुपए ब्याज की अदायगी में बढ़ोतरी के कारण है जिसके लिए अब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। रक्षा व्यय के लिए प्रावधान की राशि 1995-96 के संशोधित अनुमान में 26879 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 27,798 करोड़ रुपए कर दी गई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि यदि आवश्यक हुआ तो हमारी सशस्त्र सेनाओं को शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करने तथा उन्हें युद्ध स्थिति हेतु तैयार रखने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

73. कृषि और सिंचाई क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मुख्य नए उपायों की चर्चा में पहले ही कर चुका हूँ। फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता में पिछले वर्ष के 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 1724 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई इस आर्थिक सहायता राशि से बेहतर भूमि विकास और उत्पाद हेतु विभिन्न उर्वरकों का संतुलित उपयोग होने की संभावना है।

74. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता को भी 5500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5884 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

75. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजनाओं के अंतर्गत, भारत यंत्र निगम लिमिटेड, भारत भारी उद्योग लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनियों से संबंधित बकाया ब्याज को बट्टे खाते में डालने तथा

ऋणों की राशि को इक्विटी में बदलने के लिए 449 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण देने के लिए 1270 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जो मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए है।

76. अब मैं राजस्व प्राप्तियों की तरफ आता हूँ। कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 129,453 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। राज्यों को करों के भाग के रूप में 34,451 करोड़ रुपए प्रदान करने के पश्चात्, केन्द्र का निवल कर राजस्व 95,002 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्व जो हमारी आय का एक महत्वपूर्ण भाग है, मैं भी अच्छी वृद्धि दिखाई दी है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ, जो 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 29,103 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, इस वर्ष 33,035 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। मुझे विश्वास है कि कुछ शीर्षों के अंतर्गत, हम और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने सेलूलर तथा बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के आप्रैटर्स से लाइसेंस फीस के रूप में 2500 करोड़ रुपए का ऋण लिया है।

77. केन्द्र के लिए निवल राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें कर-भिन्न प्राप्तियाँ भी शामिल हैं, 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 110191 करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 128037 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

78. पूंजीगत प्राप्तियों के क्षेत्र में, पारम्परिक बाजार ऋणों की राशि 3700 करोड़ रुपए रखी गई है। अन्य मध्यम और दीर्घावधिक ऋणों की राशि 21,798 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल विदेशी सहायता की राशि 2461 करोड़ रुपए होगी। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के निवेश से होने वाली प्राप्तियों में से भी 5000 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूँ। कराधान की मौजूदा दरों पर कुल प्राप्तियाँ 195774 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि कुल व्यय 204698 करोड़ रुपए का होगा। मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में राजकोषीय घाटे और बजट घाटे के संबंध में और भी बहुत कुछ कहूँगा।

भाग "ख"

79. अब मैं अपने कर प्रस्तावों पर आता हूँ।

80. यह शुभ समाचार है कि केवल एक कर को छोड़कर कोई नया प्रत्यक्ष कर नहीं लगा है और मुझे विश्वास है कि उस एक मात्र नए कर का भी प्रायः व्यापक रूप से स्वागत किया जाएगा।

81. समाज के सभी वर्गों की यह जोरदार मांग रही है कि व्यक्तिगत आयकर की न्यूनतम सीमा 40,000 रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर कम से कम 60,000 रुपए कर दी जाए। न्यूनतम सीमा में 1000 रुपए की हरेक वृद्धि से राजकोष का खर्च 150 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा और चूंकि इस हानि का 77.5% राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा, इसलिए इस संबंध में कोई बड़ी रियायत देने से राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, जबकि प्रत्यक्ष कर का आधार पहले से ही सीमित है—केवल 110 लाख व्यक्ति ही आयकर देते हैं—तब कोई भी वित्त मंत्री उनमें से 20 या 30 लाख लोगों को इस परिधि से बाहर नहीं जाने दे सकता। तथापि, मैं कर की पहली परिधि में आने वाले कर-निर्धारितियों, विशेषतया वेतनभोगी वर्ग को राहत देने की जरूरत को स्वीकार करता हूँ। मैं दो तरीके से ऐसा करने का प्रस्ताव करता हूँ: सर्वप्रथम मैं पहली परिधि के लिए आयकर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह लाभ सभी कर निर्धारितियों को मिलेगा। मैं 60,000 रुपए तक की आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए

करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार 60,000 रुपए की वार्षिक आमदनी वाला एक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी भविष्य निधि में न्यूनतम अंशदान करते हुए अब किसी तरह का कोई कर नहीं देगा। यदि उसके पास किसी तरह की कोई बचत नहीं है तो भी उसे केवल 300 रुपए ही भुगतान करने होंगे।

82. हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति विशेष ध्यान देना है। इस समय, वरिष्ठ नागरिक 100,000 रुपए के आय स्तर तक 40% की विशेष कर छूट का लाभ उठाते हैं। मैं उस राशि को बढ़ाकर 120,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

83. अपने मकानों में रहने वाले उन मकान-मालिकों को राहत देने की जरूरत है जिन्होंने उधार लेकर अपने मकानों के लिए वित्त व्यवस्था की है। अपनी सम्पत्ति से होने वाली आय के लिए उन्हें अनुमत 10,000 रुपए के ब्याज भुगतान की कटौती को बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है।

84. एक अन्य राहत उपाय के रूप में, मैं किसी व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के बारे में कटौती के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80घ के अन्तर्गत 6000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

85. मैंने पहले ही भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आरम्भ की जा रही वैयक्तिक-व-परिवार पेंशन की नई योजना का उल्लेख किया है। इस रूप में बचतों को बढ़ावा देने के लिए, मैं पेंशन निधि में अंशदान देने के लिए कर-योग्य आय से प्रति वर्ष 10,000 रुपए की सीमा तक कटौती किए जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में ऐसी पेंशन निधि की आय को आयकर से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

86. इस समय सड़कों, राजमार्गों, पुलों, नए विमान पत्तनों, बन्दरगाहों और रेल प्रणालियों जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास, अनुरक्षण एवं प्रचालन में लगे हुए उद्यमों को धारा 80-झक के अन्तर्गत पौंच वर्ष का करावकाश मिला हुआ है। मैं सिंचाई, जल आपूर्ति, सफाई तथा मल निकासी प्रणालियों में निवेश के लिए यह प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूँ।

87. मैं अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए विशिष्ट रूप से स्थापित की गई कम्पनियों को आयकर अधिनियम की धारा 80-झक के अन्तर्गत पौंच वर्ष का करावकाश प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भुगतान की गई धनराशि पर आयकर अधिनियम की धारा 35(2कक) के अन्तर्गत भारित कटौती प्रदान करने के लिए किसी बाहरी निकाय द्वारा अनुमोदन की शर्त को हटाकर मौजूदा प्रक्रिया को भी सरल बना रहा हूँ।

88. आधारभूत संरचना वाली निधियां आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हैं। आधारभूत सुविधाओं के वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाने के लिए स्थापित की गई ऐसी निधियों को बढ़ावा देने के लिए मैं उन्हें आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसी निधियों या कम्पनियों को किसी आधारभूत सुविधा को विकसित करने, बनाए रखने और संचालित करने के लिए स्थापित किए गए किसी उद्यम में शेयरों या दीर्घकालिक वित्त-व्यवस्था के रूप में किए गए निवेशों से मिलने वाला कोई भी लाभांश, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ आयकर से मुक्त होगा।

89. मैं उन सार्वजनिक कम्पनियों के अनुमोदित डिबेंचरों अथवा इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति का भी प्रस्ताव करता हूँ जो धारा 88 के अन्तर्गत कर छूट की पात्र हैं बशर्ते कि ऐसे सार्वजनिक निर्गमों की प्राप्तियों को किसी नई आधारभूत सुविधा का सृजन करने के लिए या विद्युत उत्पादन या वितरण करने के लिए लगाया जाए। ऐसे निवेश के मामले में धारा 88 के अन्तर्गत 60,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया जाएगा।

90. पिछले कुछ वर्षों में कम्पनी कर की दरें कम की गई हैं और उन्हें सरल बनाया गया है जिसके परिणाम बड़े ही उत्साहवर्धक रहे हैं, इसीलिए कम्पनी करों में सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तौर पर महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पहला मुद्दा विगत में दिया गया यह आश्वासन है कि कम्पनी अधिभार अस्थायी होगा। दूसरा मुद्दा शून्य कर वाली कम्पनियों की स्थिति है जोकि, कई प्रेक्षकों के अनुसार, कर-प्रणाली में अत्यधिक शिथिलता की परिचायक है। मैं इन दोनों मुद्दों को निम्नानुसार सुलझाने का प्रस्ताव करता हूँ:

- (i) मैं कम्पनी कर पर अधिभार की दर 15% से घटाकर 7.5% कर रहा हूँ और अपने अगले बजट में भी ऐसा ही उपाय करने की आशा करता हूँ। इस घटे हुए कर भार से छोटी और बड़ी सभी कम्पनियां लाभान्वित होंगी।
- (ii) मैं कम्पनियों पर “न्यूनतम विकल्प कर” (एम.ए.टी.) लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। जहाँ सभी पात्र कटौतियों का लाभ उठाने के उपरान्त आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा परिगणित कम्पनी की कुल आय बही लाभ के 30 प्रतिशत से कम हो तो इस मामले में उस कम्पनी की कुल आय बही लाभ का 30 प्रतिशत मानी जाएगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत परिगणित प्रभावी दर बही लाभ का 12 प्रतिशत बैठती है। तथापि, विद्युत और आधारभूत क्षेत्रों में लगी हुई कम्पनियों को “न्यूनतम विकल्प कर” से छूट प्राप्त होगी।

91. विदेशी कम्पनियों की सुलना में भारतीय कम्पनियों के लिए समान स्तर पर कार्य करने की क्षमता प्राप्त करने के एक उपाय के तौर पर, मैं घरेलू कम्पनियों के मामले में दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ पर कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

92. बचत को बढ़ावा देने के लिए तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए बचतों को सरणीबद्ध करने के उद्देश्य से, मैं दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभों को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ बशर्ते कि पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले या प्रोद्भूत होने वाले निवल प्रतिफल को तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में लगाया जाए या दूसरी ओर समूचे पूंजीगत अभिलाभ को सात वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में लगा दिया जाए। कर-निर्धारिती के पास अब दो नए बचत साधनों का विकल्प होगा।

93. मैं परिसम्पत्तियों में अंश शेयर रखने वाले वित्त व्यवस्थापकों के किसी सहायता संघ द्वारा बढ़ी पूंजी वाली गहन परियोजनाओं के संयुक्त वित्त-पोषण की आवश्यकता के कारण परिसम्पत्तियों के अंश स्वामित्व के मामले में मूल्यह्रास की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

94. उद्योग में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ कि व्यापार हानियों की तरह ही अनवशोषित मूल्यह्रास को केवल आठ वर्षों की-अवधि के लिए आगे ले जाया जाएगा।

95. परिसम्पत्तियों की बिक्री-और-पट्टा-वापसी की पद्धति के कारण पट्टादायी संस्थाओं को बहुत अधिक मूल्यह्रास से गुजरना पड़ता है। इस नियंत्रित करने की जरूरत है। इसलिए, मैं आयकर अधिनियम में यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ कि बिक्री-और-पट्टा-वापसी के लेन-देनों के मामले में पट्टेदार के हाथों में, जो पहले स्वामी था, परिसम्पत्ति का अवलिखित मूल्य पट्टाकर्ता के हाथों में लागत मूल्य समझा जाएगा। वास्तविक लेन देन को प्रभावित न करते हुए भी यह उपाय घाटे में चलने वाले प्रतिष्ठानों को मूल्यह्रास के अनुचित विनिमय में संलग्न होने से बचाएगा।

96. मुझे यह अनुचित लगता है कि कर-निर्धारिती द्वारा अपने व्यापार, कार्यालय या कारखाना परिसर के रूप में प्रयोग न की जाने वाली वाणिज्यिक सम्पत्तियों धनकर की परिधि से बाहर होनी चाहिए। तदनुसार मैं इस अवांछित श्रुति को दूर करने तथा ऐसी वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर धन-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

97. कर राहत के जिन अन्य उपायों का मैंने प्रस्ताव किया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (i) कैसर या एड्स जैसी लम्बी बीमारियों, जिनके उपचार में काफी खर्च आता हो, के रोगी या उनके संरक्षक को 15,000 रुपये की विशेष कटौती की अनुमति देना।
- (ii) किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन संघ की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (24) के अन्तर्गत छूट देना।

(iii) आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शत प्रतिशत छूट प्रदान करना—

- (क) गरीबों में सबसे गरीब व्यक्तियों के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित बीमारी सहायता निधियों को किए हुए दान;
- (ख) हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित की गई राजकीय और राष्ट्रीय रक्त-आधान परिषदों को किए गए दान; और
- (ग) देश की सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थापित की गई तीन निधियों को किए गए दान। ये निधियां हैं: सेना केन्द्रीय कल्याण निधि, भारतीय नौसेना हितकारी निधि तथा वायुसेना केन्द्रीय कल्याण निधि। अपनी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर अफसरों और जवानों का अभिवादन करने का यह मेरा अपना तरीका है।

98. "सार्क" के प्रति अपने दायित्व के एक भाग के रूप में मैं "क्षेत्रीय परियोजनाओं की सार्क निधि" (एसएफआरपी) की आय को आयकर से छूट दे रहा हूँ।

99. देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अगस्त, 1995 में एक उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम स्थापित किया गया था। मैं इसकी आय को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

100. इन प्रस्तावों के कारण निगम कर के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि होने की सम्भावना है जिसका अनुमान 912 करोड़ रुपए लगाया गया है।

101. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आता हूँ।

102. पिछले कुछ वर्षों में, दरों की संख्या घटाकर, छूट समाप्त करके तथा मूल्यानुसार दरों में भारी परिवर्तन करके हमारे अप्रत्यक्ष कर ढाँचे को सुधारने के उपाय किए गए हैं। सीमा शुल्क की ओर से, वर्ष 1995-96 में शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 50% कर दिया गया जिसके साथ ही सभी वस्तुओं की दरों में तदनुसार कटौती की गई। केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में भी सुधार किया गया तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए मॉडवेट शुरू करने तथा वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रायः सभी मदों को निवेश ऋण सुविधाएं प्रदान करने से वे मूल्य वर्धित कर की ओर उन्मुख हुईं। इन परिवर्तनों ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है, कर ढाँचे को सरल बनाया है और बेहतर पारदर्शिता लाया है। उनके कारण ही राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके साथ ही दरों में पर्याप्त कटौती किए जाने के बावजूद पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष अप्रत्यक्ष कर संग्रहों में 19 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। साक्षात् न्यूनतम कार्यक्रम ने सरकार को ये कर सुधार जारी रखने का अधिदेश दिया है और मैं ऐसा करने का प्रस्ताव करता हूँ।

103. अपने उद्योग को व्यापक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने तथा संक्रान्ति काल में इसे यथोचित सुरक्षा स्तर उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं सीमा शुल्क की दरों के मामले में परिमित एवं महत्वपूर्ण उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ।

104. मेरे इन प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- कच्चे तेल तथा अन्य बुनियादी पेट्रोरसायन मध्यवर्तियों पर सीमाशुल्क में कटौती।
- कच्चे माल तथा निविष्टियों जैसे रसायन, प्लास्टिक, प्राकृतिक रबड़ और लौह तथा अलौह धातुओं पर सीमा शुल्क की दरों में कटौती।
- इलेक्ट्रानिक वस्तु क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित कच्चे माल एवं संघटकों पर सीमा शुल्क में पर्याप्त कटौती।
- सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटरों पर शुल्क की दरों में कटौती।
- वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए चुनिंदा मशीनरी पर आयात शुल्क में कटौती।
- शुल्क दरों की अनेक असंगतियों को दूर करना।
- वर्गीकरण तथा दरों से संबंधित विवादों में पर्याप्त कमी लाने के लिए समान तरह की मदों पर दरों का एकीकरण।
- केवल ऐसी छूटों का प्रतिधारण जो फिलहाल आवश्यक हों।

105. भारत रसायनों का एक प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश बन गया है। इस उद्योग ने पिछले दो वर्षों में लाभप्रद वृद्धि दर्शायी है। यही वह क्षेत्र है जिसमें भारत अपनी प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति की क्षमता का उपयोग कर सकता है और रसायनों के उत्पादन में विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बन सकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मैं निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- कच्चे माल पर शुल्क दर को 35% से घटा कर 25% करना।
- बिटूमन पर शुल्क दर को 30% से घटा कर 10% करना।
- पेट्रोरसायन निर्माण समूहों जैसे क्यूमीन, टालूइन तथा साइक्लोहेक्सेन के संबंध में 10% पर दरों का एकीकरण।
- कार्बानिक और अकार्बानिक दोनों रसायनों पर शुल्क की दरों को 50% से घटाकर 40% करना।

106. हमारे वस्त्रोद्योग में लाखों लोग लगे हुए हैं। इस आधुनिक बनाना तथा एक ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसमें इसका तेजी से विकास हो सके। इसके लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ—

- रेयान ग्रेड के लकड़ी की लुगदी पर आयात शुल्क को 25% से घटाकर 5% करना।
- एक्रिलोनीट्राइल पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% करना।
- डी.एम.टी., पी.टी.ए. तथा एम.ई.जी. पर शुल्क की दर को 35% से घटाकर 25% करना। परंतु कैप्रोलेक्टम के मामले में संशोधित शुल्क 30% करना।
- कृत्रिम और सिन्थेटिक रेशों पर शुल्क दर को 45% से घटाकर 30% करना।
- नाइलोन फिलामेन्ट यार्न, पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न तथा विस्कोस फिलामेन्ट यार्न पर शुल्क दरों को 45% तथा 40% के मौजूदा स्तरों से एक में मिलाकर 30% करना।

107. मैं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को मॉडवेट का लाभ प्रदान करते हुए उत्पाद शुल्क की व्यापक पुनर्संरचना करने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिस पर मैं कुछ समय बाद आऊंगा। मुझे विश्वास है कि इन उपायों से हमारा वस्त्रोद्योग आगामी वर्षों में बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा।

108. हमारे पावर प्लांट बदली हुई मांग तथा प्रतिस्थापित क्षमता के बेहतर उपयोग के कारण कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। मेरा नॉन-कोकिंग कोयले पर शुल्क दर को 35% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव है। मेरा कोक पर शुल्क को 25% के वर्तमान स्तर से घटाकर 20% करने का भी प्रस्ताव है।

109. हमारा प्लास्टिक उद्योग भी पूरी तरह विकसित हो रहा है। मैं प्लास्टिक पर शुल्क को 40% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक की वस्तुओं पर मैं 50% के मौजूदा शुल्क स्तर को घटाकर 40% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

110. औषधियों और भेषजों पर शुल्क की दरों के संबंध में मैं जीवन रक्षक औषधियों पर शुल्क की शून्य दर बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अन्य सभी एलोपैथिक दवाइयों पर भी शुल्क की दर 50% से घटाकर 40% करने का प्रस्ताव करता हूँ। सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली चिकित्सा संबंधी पशु औषधियां उपलब्ध कराने के लिए मैं पशु-चिकित्सा संबंधी विनिर्दिष्ट औषधियों पर निर्धारित दर 15% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

111. उद्योग जगत की यह निरन्तर शिकायत रही है कि धातुओं पर सीमा शुल्क बहुत अधिक है तथा इससे अनुप्रवाही उद्योग, विशेषतया पूंजीगत माल के लिए प्रतिस्पर्धी हो पाना कठिन हो जाता है। उद्योग जगत की यह मांग रही है कि धातुओं पर शुल्क की दर में पर्याप्त कमी की जानी चाहिए। तथापि, अपने धातु उद्योग को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के अनुरूप स्वयं

को समर्पित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस करते हुए मैं निकल और अल्यूमीनियम को छोड़कर सभी धातुओं पर इस समय लागू 35% या 40% की दर में मामूली कमी करके उसे 30% की उच्चतम दर पर लाने का प्रस्ताव करता हूँ। अपरिष्कृत अल्यूमीनियम और अपरिष्कृत निकल के संबंध में, मैं वर्तमान स्तर को क्रमशः 10% तथा 20% पर बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं परिष्कृत अल्यूमीनियम पर शुल्क को 25% से घटाकर 20% तथा परिष्कृत निकल पर 30% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

112. हालाँकि मैं मशीनरी की शुल्क दर, जो 25% है, में हेर-फेर नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं रेलवे, विमानपत्तन, समुद्री बन्दरगाह, आदि के लिए सिगनल व्यवस्था तथा सुरक्षा उपकरण पर 50% के वर्तमान शुल्क स्तर को घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

113. विगत तीन वर्षों में हमारे इलेक्ट्रानिक उद्योग ने असाधारण प्रगति की है जो कि उद्यम और साथ ही सीमा शुल्क में पर्याप्त कटौती करने से मिलने वाली उत्प्रेरणा का प्रतिफल रहा है। इस प्रवृत्ति को कायम रखने के लिए मैं निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूँ:

- कच्चे माल पर, मौजूदा 15% से 10%।
- संघटकों पर, 25% से 20%।
- रंगीन टी.वी. के लिए ग्लास शेल पर, 30% से 25%।
- रंगीन पिक्चर ट्यूब पर, 40% से 30%।
- कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर उपकरणों पर, 40% से 20%।
- तैयार माल पर 50% की शुल्क दर जारी रहेगी।

114. देश में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, मैं खेल के सामानों पर आयात शुल्क को 50% से घटाकर 30% करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

115. पेशेवर प्रेस फोटोग्राफरों को राहत देने के लिए, मैं उन्हें एक लाख रुपए तक के फोटोग्राफी उपकरण निःशुल्क आयात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रतिष्ठित पत्रकारों को भी व्यक्तिगत कम्प्यूटर, टाइपराइटर तथा फैक्स मशीन आयात करने के लिए इसी तरह की रियायत दी जा रही है।

116. दूरसंचार एक प्रगतिशील क्षेत्र है और यह हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन-रेखा सिद्ध होगा। दूरसंचार के प्रभावशाली नेटवर्क का अस्तित्व त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक पूर्वपिका है। दूरसंचार विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, मेरा यह प्रस्ताव है कि दूरसंचार उपकरण के पुर्जों और उप-साज सामानों पर शुल्क 35% से घटाकर 30% तथा तैयार उपकरणों पर शुल्क 50% से घटाकर 40% कर दिया जाए। सेल्यूलर फोनो, पेजरों और ट्रकिंग

हेण्डसेटों की तस्करी करने के प्रलोभन से बचने के लिए, मैं उन पर सीमा शुल्क को घटाकर 30% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

117. देश में चिकित्सा स्तरों का उन्नयन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं विनिर्दिष्ट उपकरण, जोकि सामान्यतया भारत में निर्मित नहीं किए जाते, और उनके पुर्जों पर शुल्क की दर को 15% से घटाकर 10% और अन्य चिकित्सा उपकरणों पर 40% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

118. इस समय खाद्य तेलों पर शुल्क की दर 30% है। यह जन सामान्य के दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण मद है और हमारे देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त कमी है। मैं खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

119. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले अपने भाषण में आधारभूत संरचना में निवेश की गति बढ़ाने की अत्यावश्यकता पर जोर दिया था। मैंने उन क्षेत्रों का ब्योरा भी दिया था जिनके लिए मेरा अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव है। मुझे इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हैं। मैं आयातकों से यह कहना चाहूँगा कि वे इस देश में आधारभूत संरचना के निर्माण का बोझ मिलकर उठाएँ क्योंकि अन्ततः इससे उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं शून्य शुल्क कर वाली वस्तुओं के आयातों या विभिन्न शुल्क मुक्त लाइसेंसों के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए सीमा शुल्क की शून्य दर पर आयातित वस्तुओं को छोड़कर सभी आयातों पर 2% विशेष सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कराधान पात्र यात्रियों द्वारा अथवा विशेष आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातित सोने और चांदी पर लागू नहीं होगा। इससे चालू वर्ष में लगभग 1600 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है।

120. आयातक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी, 1996 में आयात संबंधी वित्त पर लगाए गए 25% के ब्याज दर अधिभार को आज वापस लेने की घोषणा कर रहा है।

121. अब मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अपने प्रस्तावों पर आता हूँ। आज संसार के अधिकतर देशों के पास मूल्य वर्धित कर प्रणाली है जिसे वस्तु कराधान का अत्यधिक कारगर ढाँचा स्वीकार किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी है कि कुछ राज्य सरकारें इस मूल्य वर्धित कर प्रणाली को अपनाने जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों के सुधारों ने हमें एक केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली (वीएटी) के अधिक निकट लाया है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कानूनी बाधाएँ हैं।

122. हमारे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की संरचना में अभी भी 11 यथामूल्य दरें हैं। ये दरें 0 से 50 प्रतिशत तक पायी जाती हैं। आदर्श रूप में उत्पाद शुल्क की केवल चार दरें होनी चाहिए—शून्य, व्यापक खपत वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की निम्न दर, अन्य सभी वस्तुओं पर एकल सामान्य दर तथा विलासिता की वस्तुओं पर उच्चतर दर। इस कर संरचना की ओर अग्रसर होना

हमारे लिए नितान्त आवश्यक है ताकि हम बेकार की मुकदमेबाजी को समाप्त कर सकें और हमारी कर संरचना पारदर्शी और सरल हो सके। चालू वर्ष में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बजट तैयार करने में मुझे जितना समय मिला था उतने समय में यह कार्य संभव नहीं था। तथापि, मैं इस वर्ष यह पहला कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूँ और मुझे विश्वास है कि हम अगले एक या दो वर्ष में चार दरों वाली उत्पाद शुल्क संरचना प्राप्त कर लेंगे।

123. मैं वस्त्रोद्योग क्षेत्र में मॉडवेट का सिद्धान्त अपनाकर वस्त्रोद्योग क्षेत्र पर कर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मुख्य धारा के साथ मिलाने का प्रस्ताव करता हूँ। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इस समय रेशे और सूत (यार्न) की अवस्था में उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं और कपड़ों पर बिक्री कर के बदले केवल एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है। यह कराधान का एक अत्यन्त अकुशल तरीका है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निविष्टियों पर बहुत अधिक शुल्क लगता है जिससे अपवचन को बढ़ावा मिलता है, इससे मूल्य संयोजन नहीं होने पाता है; और इससे उद्योग जगत को पूंजीगत माल, रसायन तथा सूत (यार्न) पर मॉडवेट निवेश ऋण मांगने का अवसर नहीं मिल पाता है। हालांकि अन्य उद्योगों का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है, फिर भी इस असंतुलित कर संरचना के कारण हमारा वस्त्रोद्योग इस प्रक्रिया में पूर्णरूपेण भागीदार नहीं हो सका है। इसलिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ।

124. मैं पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न के मामले में यार्न पर उत्पाद शुल्क को 50% के वर्तमान स्तर से घटाकर 40% करने तथा दूसरे यार्न पर दरों को एकीकृत करके 20% करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अन्तर्गत नाइलोन फिलामेन्ट यार्न और सूती यार्न शामिल नहीं हैं जिनके लिए क्रमशः 30% और 5% की वर्तमान दरें कायम रखी जाएंगी। वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए मॉडवेट की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं सूती कपड़ों पर 5% और अन्य कपड़ों पर 10% का मूल उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसे कपड़े की संसाधित अवस्था में संगृहीत किया जाएगा। संसाधक इस आधार पर कि यार्न को मूल्य तैयार कपड़े के 50% हो, आरोपित यार्न पर प्रदत्त शुल्क को मॉडवेट के अनुसार लाने की स्थिति में होंगे। मैंने आरोपित मूल्य की एक सरल प्रक्रिया अपनायी है ताकि ऐसे दूसरे कपड़ों पर मूल शुल्क न लगाया जा सके जो हजारों बिजली चालित करघों द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। इसलिए ऐसे बिजली चालित करघे उत्पाद शुल्क की परिधि से बाहर बने रहेंगे। संयुक्त कारखाने और वस्त्र संसाधक उन मॉडवेट सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे जो अब तक उन्हें नहीं मिली थीं। वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए चुनिंदा मशीनरी तथा निविष्टियों पर सीमा शुल्क में पर्याप्त कटौती के साथ-साथ उत्पाद शुल्क की इस पुनर्संरचना से वस्त्रोद्योग को अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इससे परिधान (गार्मेंट) निर्यातकों के लिए शुल्क वापसी की दरों का हिसाब लगाना भी आसान हो जाएगा।

125. सीमा शुल्क संबंधी अपने प्रस्तावों में मैंने कच्चे तेल पर सीमा शुल्क को 35% से कम करके 25% करने का प्रस्ताव किया है। यह शुल्क संरचना के पुनर्गठन एवं युक्तिकरण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कार्यक्षम परिष्करणशालाओं को बढ़ावा देना तथा शुल्क को निवेश अवस्था से उत्पाद अवस्था में अन्तरित करना है। मैं एलपीजी तथा मिट्टी के तेल को छोड़कर सभी

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 10% से ऊपर की ओर 15% पर समजित करके सीमा शुल्क की हानि को पूरा करने का प्रस्ताव करता हूँ। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में दोनों को मिलाकर प्रस्तावित परिवर्तनों से राजस्व निष्प्रभावी है तथा इनका पेट्रोलियम उत्पादों की प्रवर्तित कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

126. माननीय सदस्य यह जानते हैं कि व्यापक उपभोग वाली प्रायः सभी वस्तुओं को पहले से ही उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है और बड़े पैमाने पर खपत वाली अन्य बहुत सी वस्तुओं की उत्पाद शुल्क दर केवल 10% है। मैं कुछ और वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। वे हैं:

- (क) वनस्पति और मार्गरीन;
- (ख) सभी राजकीय पाठ्य पुस्तक निगमों को दिए जाने वाले लेखन एवं मुद्रण कागज;
- (ग) पशु वसा तथा तेल;
- (घ) एस्बेस्टोस फाइबर;
- (ङ) धातु अयस्क; और
- (च) टैपियोका उत्पाद।

127. मैं निम्नलिखित वस्तुओं पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूँ:

- (क) दूध पेस्ट, 20% से 10%;
- (ख) फिटर्जेण्ट, 30% से 25%;
- (ग) कागज और गत्ते के बने डिब्बे, पेटियाँ और थैले 20% से 10%;
- (घ) अर्ध-स्वचालित प्रक्रिया द्वारा निर्मित काँच के बर्तन, 20% से 10%;
- (ङ) मेज, रसोई, आदि के काम आने वाले शीशे के सामान, 15% से 10%;
- (च) एस्बेस्टोस सीमेंट की वस्तुएँ, 25% से 20%; और
- (छ) चमकदार टाइलों को छोड़कर मिट्टी की वस्तुएँ, 20% से 15%।

128. मैं जूते के लिए छूट सीमा प्रति जोड़े 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

129. मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क की दरें ऐसे वाहनों के स्वीकृत वर्गीकरण के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए मैं निम्नलिखित युक्तिकरण का प्रस्ताव करता हूँ:

- (क) जो मोटर कारें तथा अन्य मोटर वाहन मुख्यतः चालक को छोड़कर छः से अनधिक व्यक्ति ले जाने के लिए होते हैं, उन पर शुल्क 40% पर अपरिवर्तित रहेगा।

(ख) जो मोटर वाहन मुख्यतः चालक को छोड़कर छः से अधिक व्यक्ति लेकिन 12 से अनधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए होते हैं, उन पर शुल्क—20%.

(ग) व्यक्तियों या सामान के परिवहन के लिए अन्य मोटर वाहनों पर शुल्क—15%.

दुपहियों या ट्रैक्टरों पर शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

130. यदि कोई एक ऐसा भी क्षेत्र है जिसमें कोई वित्त मंत्री कर भी लगा सकता है और लोगों को खुश भी रख सकता है, तो वह सिगरेट है। लेकिन आज सिगरेटों पर लगभग 5% से लेकर $7\frac{1}{2}\%$ तक विशिष्ट शुल्क में मामूली वृद्धि का प्रस्ताव करके मैं आप लोगों को थोड़ा ही खुश कर पाऊँगा। नॉन फिल्टर सिगरेटों के मामले में, जिनकी लम्बाई 60एमएम से अधिक नहीं है जो सामान्यतया छोटे सिगरेट कहलाते हैं, मैं कर में 25% तक की वृद्धि करके उनका मूल्य 60 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति हजार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

131. भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं भारत और साथ-साथ विनिर्दिष्ट देशों में विकसित एवं पेटेन्ट वाली वस्तुओं को तीन वर्षों की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अनुसंधान और विकास संस्थाओं के लिए उपस्कर तथा उपभोग्य वस्तुओं के आयात हेतु सीमा शुल्क से छूट को भी युक्तिसंगत बना रहा हूँ।

132. मैंने लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत शुल्क छूट के लिए पात्र वस्तुओं की सूची में पोटेशियम क्लोरेट, तांबे का चूर्ण तथा सिगरेट लाइटर शामिल करने का प्रस्ताव किया है। अन्यत्र प्रस्तावित आयात शुल्कों में कटौती से भी लघु उद्योगों को भरपूर लाभ मिलेगा। दियासलाई के सैकड़ों लघु विनिर्माताओं को लाभान्वित करने के लिए, मैंने उन पर लागू वास्तविक नियंत्रण प्रणाली को समाप्त करने तथा उन्हें दिन-प्रति-दिन की नियंत्रण परेशानी से मुक्त करते हुए स्व निष्कासन प्रक्रिया लागू करने का निर्णय किया है। मुझे आशा है कि दियासलाई की लघु उद्योग इकाइयों से उत्पाद शुल्कों के भुगतान में पर्याप्त वृद्धि होगी।

133. मैंने सीमा शुल्क तथा अन्य बहुत से लघु क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क दोनों में ही दरों और छूटों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। मैं इनका ब्योरा देकर सदन का समय लेना नहीं चाहूँगा।

134. हमारी उत्पाद शुल्क प्रक्रिया पुरानी है और समय के अनुरूप नहीं है। उन्हें संशोधित किए जाने की जरूरत है। उन्हें करदाताओं द्वारा कर कानूनों का स्वेच्छिक अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1 अक्टूबर, 1996 से कर-निर्धारितियों को अब मासिक विवरणियों के साथ-साथ बीजकों की प्रतियाँ प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पाद शुल्क विभाग को अब उन्हें सिर्फ एक सामान्य विवरणी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें स्व-मूल्यांकन आधार पर भुगतान किए गए शुल्क का उल्लेख किया जाएगा। जहाँ भी संभव हो, कर निर्धारितियों के कम्प्यूटरों को सतत सक्रिय मूल्यांकन के लिए विभागीय कम्प्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है।

135. मैं उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा चयनात्मक लेखा-परीक्षा की एक योजना शुरू करने तथा कर-निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और दस्तावेजों की नैमित्तिक जांच-पड़ताल करने की मौजूदा योजना समाप्त करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह योजना भी 1 अक्टूबर, 1996 से प्रवृत्त होगी।

136. मुझे विश्वास है कि जिन विनिर्माताओं को उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होता है वे इन परिवर्तनों का व्यापक रूप से स्वागत करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि वे कानूनों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करेंगे। तथापि, मैं सरकार के इस संकल्प की अभिपुष्टि करना चाहता हूँ कि कर-वंचकों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मैं छल-कपट, सोंठ-गोंठ, गलतबयानी या तथ्यों को छुपाने के कारण कर-वंचन के लिए ब्याज सहित अनिवार्य जुर्माना लगाने की व्यवस्था करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिनियमों में यथोचित परिवर्तन करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। अब से इन आधारों पर शुल्क अपवंचन के लिए अनिवार्य जुर्माना शुल्क अपवंचन की राशि के बराबर होगा। कर अपवंचकों को जिस महीने में शुल्क अपवंचन की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था उसके अगले माह के पहले दिन से लेकर ब्याज का भुगतान भी करना होगा तथा फौजदारी मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा।

137. अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 हमें उस औपनिवेशिक युग की याद दिलाते हैं जब नमक पर उत्पाद शुल्क लिया जाता था। नमक पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है और इसलिए नमक का संदर्भ पुराना हो गया है। मैं नमक पर उत्पाद शुल्क से संबंधित सभी संदर्भों को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

138. मॉडवेट योजना को, जिसमें निविष्टियों और पूंजीगत माल पर शुल्क संबंधी ऋण के लिए व्यवस्था की गई है, पिछले कुछ वर्षों में काफी उदार बना दिया गया है। अभी भी कतिपय निविष्टियों तथा पूंजीगत माल को शामिल किए जाने के बारे में समस्याएँ हैं। मैं मॉडवेट नियमों में पूंजीगत माल से संबंधित टैरिफ के शीर्षक एवं उप-शीर्षकों का उल्लेख करते हुए पात्र पूंजीगत माल के क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह भी चिन्ता का विषय है कि मॉडवेट ऋण योजना का दुरुपयोग होता है। इस समय, उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत कोई भी डीलर मॉडवेट बीजक जारी कर सकता है और इस सुविधा का स्पष्ट तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं डीलरों द्वारा दो चरणों तक मॉडवेट-योग्य बीजकों के निर्गम को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मॉडवेट ऋण के गलत उपयोग करने के मामले में ब्याज की वसूली करने और मॉडवेट सुविधा के दुरुपयोग के लिए अनिवार्य जुर्माना लगाने के लिए मॉडवेट नियमों में उपयुक्त प्रावधान भी किए जा रहे हैं।

139. सेवाओं पर कर को स्थायी माना जाने लगा है। इस कर आधार का विस्तार करने की दृष्टि से, मैं विज्ञापन सेवाओं, रेडियो पेजिंग सेवाओं और कूरियर सेवाओं को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूँ। इन सेवाओं पर कर की दर 5% होगी। हालांकि परे वर्ष मैं इस उपाय से 150 करोड़ रुपए की आय होने की आशा है, फिर भी मैं खालू वर्ष में सिर्फ 70 करोड़ रुपए का ही आकलन कर रहा हूँ।

140. सीमा शुल्क में कटौती से संबंधित मेरे प्रस्तावों से चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में 650 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, विशेष सीमा शुल्क से होने वाली प्राप्तियों को, जो 1600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क के राजस्व में 950 करोड़ रुपए का निवल अभिलाभ होगा।

141. अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों सहित उत्पाद शुल्कों के मामले में 760 करोड़ रुपए का अभिलाभ होने का अनुमान है। इसमें से राज्यों को उनके उत्पाद शुल्क के हिस्से के रूप में 384 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है।

142. अब मुझे अपने सहयोगी संचार मंत्री की ओर से कुछ कहना है। डाक दरें, जिनमें से कुछ दरे पिछली बार 1990 में संशोधित की गई थीं, अधिकांश सेवाओं की प्रत्यक्ष लागत को भी पूरा नहीं कर पाती हैं जिसके कारण बजटीय सहायता बढ़ रही है। इतना होते हुए भी साधारण पोस्टकार्ड, पत्र, पार्सल तथा अन्य डाक सेवाओं की दरों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। केवल दो सेवाओं के संबंध में, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, मामूली वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मुद्रित पोस्टकार्ड की दर 60 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए की जा रही है तथा पंजीकरण शुल्क 6 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए किया जा रहा है। "प्रतियोगिता पोस्टकार्ड" नामक एक नई श्रेणी का पोस्टकार्ड शुरू करने का निर्णय भी किया गया है, केवल मात्र जिसको ही दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका में या के माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस श्रेणी के पोस्टकार्ड का टैरिफ 2 रुपए निर्धारित करके अवांछित आर्थिक सहायता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित की गई तारीख से प्रभावी होंगे। प्रस्तावित संशोधनों से वर्ष 1996-97 में 38 करोड़ रुपए के अल्प राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है, फिर भी डाक घाटा काफी रह जाता है।

143. सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्कों में उपर्युक्त परिवर्तनों को प्रभावी बनाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां यथा-समय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

144. मेरे बजट प्रस्तावों में व्यय और राजस्व दोनों ही पक्षों के कई निहितार्थ हैं। फिर भी माननीय सदस्यों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि अन्तिम परिणाम सन्तोषजनक है। 1996-97 में राजस्व घाटा 31,475 करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% बैठता है जो संशोधित अनुमान 1995-96 के 33,331 करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद के 3% की अपेक्षा काफी कम है। राजकोषीय घाटा वर्ष 1996-97 में 62,266 करोड़ रुपए होगा जोकि संशोधित अनुमान 1995-96 के 64,010 करोड़ रुपए के आंकड़े की अपेक्षा कम है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में पिछले वर्ष के 5.9% की तुलना में वर्ष 1996-97 का राजकोषीय घाटा 5% है। अपने अगले बजट में, मैं बेहतर कार्य करने और राजकोषीय घाटे को 4% से नीचे लाने की दिशा में अग्रसर होने की आशा करता हूँ।

145. अध्यक्ष महोदय, अब अन्त में मैं स्वयं अपने आप से पूछता हूँ कि बजट किसके लिए

होता है ? हालाँकि यह अर्थव्यवस्था के सुधार का एक मापदंड है, फिर भी यह लोगों के परिश्रम एवं अभिलाषाओं का एक दर्पण भी है। 2000 साल पहले, सन्त तिरुवल्लुवर ने राजा के मन्त्रियों के लिए सुशासन का उल्लेख किया था:

"इयात्रलुम, इत्तालुम, कत्तालुम, कत्ता
वकुघालम वल्लथ अरासु"

("सम्पत्ति को बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना, तथा उसका सही-सही वितरण करना ही, एक अच्छे प्रशासक की योग्यता को दर्शाता है।")

146. मैंने गरीबों पर कोई भार डाले बिना राजस्व बढ़ाने, कृषि, सिंचाई, आधारभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने, न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक निधियाँ उपलब्ध कराने, वेतनभोगी तथा मध्यम वर्गों को कर राहत देने तथा बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। मैंने प्रारम्भ में जिन सात उद्देश्यों की घोषणा की थी, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया है।

147. साक्षात् न्यूनतम कार्यक्रम का यह दृष्टिकोण पूर्णतया सही है कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद को अगले 10 वर्षों में प्रति वर्ष 7% से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

148. मेरा विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था की वक्र रेखा अधिक संवृद्धि की ओर अभिमुख है। विवेक इसी में है कि हम इस वक्र रेखा पर बने रहें। ऐसा करने के लिए, हमें कम सुधारों की नहीं बल्कि और अधिक सुधारों की जरूरत है। हमें कम संसाधनों की नहीं बल्कि और अधिक संसाधनों की जरूरत है। हमें कम अनुशासन की नहीं बल्कि अधिक अनुशासन की जरूरत है। और हमें कम सहानुभूति की नहीं बल्कि अधिक सहानुभूति की जरूरत है। यदि हम साक्षात् न्यूनतम कार्यक्रम का निष्ठापूर्वक अनुपालन करें तो हम अपनी मुसीबतों पर काबू पा लेंगे तथा भारत को विश्व के राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में ले जा सकेंगे। मेरे इस पहले बजट में, मुझे आशा है, उत्साह और सहानुभूति, सुधार और संयम तथा विकास एवं सामाजिक न्याय को ठीक-ठीक अनुपात में संयुक्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

149. अध्यक्ष, महोदय इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

सी. एम. चासुदेव, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1996

No. F. 15(30)-B(D)/96.—The following is published for general information :—

BUDGET 1996-97

Speech of Shri P. Chidambaram, Minister of Finance

22nd July, 1996

PART A

Sir,

I rise to present the regular budget for the year 1996-97.

2. An unusually peaceful general election produced an unusually complex mandate. It was the duty of every political party to be faithful to that mandate. Accordingly, political parties of different complexions and different ideologies have come together to form this government. Many of them are regional parties, albeit with a national outlook. What has united us is a resolve to preserve India's secular heritage and to provide a representative government committed to faster economic growth and enhanced social justice.

3. The United Front is a coalition. Before assuming office, the partners of the coalition finalised a document called "A Common Approach to Major Policy Matters and a Minimum Programme", popularly called the CMP. This historic document was released to the nation by our Prime Minister, Shri Deve Gowda, on June 4, 1996. When I began work on the CMP I was not even a Minister. When we completed our exercise I found myself in the office of Finance Minister. Therefore, my commitment to the CMP goes beyond the office I hold. Hon'ble Members will have many opportunities this afternoon to test my commitment and they will find that the CMP has provided the foundation and set the agenda for this Budget.

4. An Update of the Economic Survey 1995-96 was laid on the Table of the House last Friday. It is a slim document of no more than 21 pages and I hope it made for good weekend reading. Our conclusions are that the economic indicators point to high growth but there are significant areas of weakness. The Update has identified these areas as the fiscal deficit, sluggish agricultural growth, inadequate infrastructure, high interest rates and the trade deficit. The most worrisome is the decline in the growth of agricultural crop production to 0.9 per cent in 1995-96. The Update has also listed fiscal challenge, infrastructure challenge and employment and poverty alleviation as key issues which need to be addressed on a priority basis.

5. The CMP has declared that the government will follow economic policies that will promote growth with social justice and lead to greater self-reliance. We have no use for jobless growth; nor for growth that leaves untouched large sections of the people. We will remove controls and regulations over agriculture and industry. We will keep our economy open and competitive in order to encourage more foreign trade and attract more foreign investment. We will reform the tax system. We will broaden and deepen reforms of the financial and capital markets even while strengthening independent regulators like the Reserve Bank of India (RBI) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI). Above all, we will observe fiscal and monetary prudence which is the key to low inflation and rapid growth.

6. This Budget, therefore, has seven broad objectives:

- To remain steadfast on the course of economic reforms and liberalisation aimed at accelerating economic growth.
- To address the concerns of the poor and provide them with basic minimum services in a time-bound manner.
- To ensure broad-based growth in agriculture, industry and services to achieve high employment.
- To ensure fiscal prudence and macro-economic stability.
- To enhance investment, especially in the infrastructure sectors.
- To strengthen key interventions to promote human development.
- To ensure viability in the balance of payments through strong export performance and larger foreign investment flows.

I shall now deal with the major areas of the economy and spell out our policy initiatives in order to achieve the objectives that I have just listed.

Agriculture & Rural Credit

7. The Common Minimum Programme lays emphasis on broad-based agricultural development and calls for a doubling of the flow of credit to agriculture and agro-industries, particularly to small and marginal farmers, within five years. We have evolved an integrated plan consisting of several elements for fulfilling this important objective.

8. First, the share capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will be increased from the present level of Rs.500 crore to Rs.2,000 crore in the next five years. I propose to double NABARD's paid up share capital to Rs.1,000 crore in the current year. A budgetary provision of Rs.100 crore is being made towards the Government of India's share and the balance Rs.400 crore will be contributed by the Reserve Bank of India.

9. Second, the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) which is operated by NABARD and funded by contributions from commercial banks falling short of their priority lending targets will be augmented considerably. The RIDF provides loans to State governments for completion of projects in areas like medium and minor irrigation, soil conservation and watershed management. During 1995-96, NABARD sanctioned loans aggregating Rs.1,984 crore to 19 States for completing 2,489 projects. During the current financial year, an additional Rs.2,500 crore will be made available for financing rural infrastructure through the RIDF.

10. In addition to the RIDF, I am proposing an Accelerated Irrigation Benefit Programme under which the Centre will provide, on a matching basis, additional Central assistance by way of loans to the States for the timely completion of selected large irrigation and multi-purpose projects. I am making an allocation of Rs.800 crore in 1996-97 to launch this scheme which is designed to accelerate the completion of irrigation projects where the project cost exceeds Rs.1,000 crore and is beyond the resource capability of the States. I am also

allocating Rs.100 crore in the current financial year for irrigation projects where, with just a little additional resources, the projects could be completed and farmers could get the benefit of assured water supply. 100,000 hectares will be brought under irrigation through these schemes and I have been assured that the first crop will be harvested on these lands during one of the next four agricultural seasons. Details of the large projects and the projects to benefit 100,000 hectares will be announced by the Planning Commission in the next few days. This programme will be closely monitored by the Department of Programme Implementation.

11. Fourth, to promote investment in commercial or high technology agriculture and allied activities such as horticulture, floriculture and agro-processing, state level agricultural development finance institutions are proposed to be set up. NABARD will be the chief promoter. Other national level financial institutions as well as the State governments concerned will be requested to participate in the equity.

12. Fifth, it has been agreed with RBI to promote the setting up of new private local area banks with jurisdiction over two or three contiguous districts. This would enable the mobilisation of rural savings by local institutions and, at the same time, make them available for investments in the local areas.

13. Finally, we have taken a number of decisions that will directly benefit the farmers. Two weeks ago, the Prime Minister announced increases in the subsidies for phosphatic and potassic fertilisers. Government have decided to extend the subsidy under the Integrated Cereal Development - Rice Programme to power tillers at the rate of Rs.30,000 or 50% of the cost for each power tiller. The subsidy scheme on small tractors at the rate of Rs.30,000 per tractor is presently restricted to small and marginal farmers. I am extending this scheme to all farmers. I am also enhancing the subsidy on sprinkler and drip irrigation from 50% to 70% of the cost of the system and the ceiling is also being raised from Rs. 15,000 to Rs.25,000 per hectare. In respect of small and marginal farmers, women and scheduled castes and scheduled tribes, this limit is being raised to 90% of the cost of the system.

Basic Minimum Services

14. One of the first acts of the Prime Minister, Shri Deve Gowda, was to convene a meeting of Chief Ministers on Basic Minimum Services. This reflects the resolve of the United Front to "advance the principles of political, administrative and economic federalism". The Chief Ministers' Conference recommended adoption of seven objectives to be attained by the year 2000. These are 100% coverage of provision of safe drinking water; 100% coverage of primary health centres; universalisation of primary education; public housing assistance to all shelterless poor families; extension of the mid-day meal scheme; road connectivity to all villages and habitations; and streamlining the public distribution system targeted to families below the poverty line.

15. These objectives are now being served by Centrally-sponsored schemes and schemes in State Plans. Hon'ble Members will be glad to know that I am providing an additional amount of Rs.2,466 crore as Central assistance for State and UT plans to significantly increase the availability of funds for these schemes. From this amount, it is our intention to allocate about Rs.250 crore to provide shelter and other basic amenities to slum dwellers. The distribution of this enhanced allocation across the seven schemes and across States and Union Territories will be determined by the Planning Commission in consultation with them.

Infrastructure Financing

16. The Update of the Economic Survey has highlighted the enormous challenge on the infrastructure front. The state of our infrastructure - particularly power and roads - is very poor. We cannot sustain a 7 per cent growth unless we can revitalise these infrastructure sectors. Huge funds are also required for telecom, railways and ports.

17. Infrastructure needs long-term finance, typically 15-20 year financial instruments. However, it has not been possible to float such instruments in the Indian market so far. Hence, I am proposing the establishment of an Infrastructure Development Finance Company (IDFC). This company will be incorporated with an authorised share capital of Rs.5,000 crore. The Central

government, the RBI, banks and financial institutions will contribute to the share capital. I am making a budgetary provision of Rs.500 crore in the current financial year as the contribution of the Central government. The RBI's initial contribution to the share capital will also be Rs.500 crore. Among other things, the IDFC will act as a direct lender, as a refinancing institution and as a provider of financial guarantees. I believe that the IDFC will induce investors, both Indian and foreign, to make available long-term funds at the lowest possible market rates.

18. I am also proposing some tax incentives for infrastructure investment which I shall outline later.

19. Hon'ble Members are aware that the Central government has already set up the National Highway Authority of India. We need a world-class national highway system in place very quickly. I have decided to provide a sum of Rs.200 crore to strengthen the capital base of the National Highway Authority of India. The Authority will now be in a position to leverage resources for highway development from both within India and from outside.

Small Scale Industry

20. The entrepreneur-driven small-scale sector forms the backbone of our industry. I am deeply committed to strengthening this sector. The following set of measures will be put in place immediately.

- First, the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has an unutilised corpus of about Rs.175 crore in its Technology Development and Modernisation Fund Scheme. I am now proposing that SIDBI should refinance the State Financial Corporations (SFCs) and commercial banks for modernisation projects upto Rs.50 lakh. This will decentralise decision-making to the advantage of small-scale units seeking modernisation funds from SFCs and banks.
- Second, refinance is now provided for the Single Window Scheme of SFCs etc. for composite loans upto Rs.50 lakh. I am doubling this ceiling to Rs.100 lakh.

- Third, SIDBI will participate in venture capital funds set up by public sector institutions as well as private companies upto 50% of the total corpus of the fund, provided such a fund is dedicated to the financing of small-scale industry.
- Fourth, in order to encourage a larger number of small scale units to seek ISO 9000 certification of quality, lending institutions will be permitted to lend to the ultimate borrowers on the same terms and conditions as SIDBI's direct lending scheme. SIDBI will provide refinance assistance to these lending institutions.

Science & Technology

21. Science and technology is the key to economic progress and prosperity. Indian scientists and technologists have accomplished a great deal, especially in the areas of agriculture, space, atomic energy and defence. There is now need for a massive renewal of our science and technology infrastructure.

22. I propose to extend a matching one-time grant for the modernisation of the laboratories and institutes of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and the Indian Council of Agricultural Research (ICAR). I will match every commercial rupee that the CSIR and ICAR earn incrementally in the next two years with another rupee from the Budget.

23. I also propose to strengthen the Fund for Technology Development and Application which was created in 1994-95 to help indigenously developed technologies reach the stage of commercial application. The interim Budget had provided Rs.10 crore. As a demonstration of this government's commitment to science and technology, I am immediately making available Rs.30 crore. The Department of Science & Technology will announce the constitution of the Technology Development Board shortly.

Public Distribution System

24. The Common Minimum Programme states that the Public Distribution System will be strengthened to meet the twin objectives of price stability and making available essential articles to the poor. It is, therefore, proposed to restructure the

PDS. A beginning will be made where the need is most acutely felt. The restructured PDS will serve households below the poverty line. Details of the restructured PDS are being worked out and will be announced in due course.

Pay Commission

25. The Fifth Pay Commission is expected to submit its report by the end of September 1996. Funds have been provided in this Budget as well as the Railway Budget to meet the anticipated expenditure. Meanwhile, I am happy that the question of granting another instalment of interim relief has been sorted out satisfactorily.

Other Welfare Measures

26. The Prime Minister has repeatedly declared that this government is a government of the poor and for the poor. Growth with social justice will be the motto of this government. Unless the country's GDP grows at over 7% per year in the next 10 years, we will not be able to abolish poverty and unemployment. However, there is a need to identify vulnerable sections of the people and help them. The Prime Minister has identified some target groups which deserve to be helped and I am proposing some new initiatives for meeting their special needs. These initiatives will be implemented through the State governments and, as far as possible, in collaboration with non-governmental organisations.

I am setting apart, initially, a sum of Rs.5 crore to assist in the establishment of old-age homes and another sum of Rs. 5 crore to assist in the establishment of residential primary schools for poor children irrespective of caste or creed. It is intended that both these programmes should be implemented through non-governmental organisations. The programmes will be firmed up by the Ministries concerned in consultation with the State governments.

- Rs.10 crore is being provided for giving assistance to States which have or will set up Women Development Corporations. An additional amount of Rs.10 crore has been set apart for starting training-cum-production centres or schemes for destitute women in different States.

I am creating a National Illness Assistance Fund with an initial corpus of Rs.5 crore. Besides, Rs.25 crore have

been set apart for contributions to the corpus of State Illness Assistance Funds that we would encourage the State governments to establish. 100% of the donations to these funds will be exempt from income tax. These funds will be used to provide assistance to the very poor for surgery or treatment for serious illnesses requiring hospitalisation.

- Rs.5 crore is being provided to award an ex-gratia amount of Rs.50,000 per family to the families of lorry and bus drivers who meet with fatal accidents. This will be implemented by the State governments on a reimbursible basis.
- I am making a provision of Rs.5 crore for building residential facilities for *hamals* - our brothers who toil day and night. This scheme will also be implemented by the States.

27. Government will consider a scheme of financial assistance to States who confer ownership rights in respect of minor forest produce on Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other weaker sections who work in forests.

Fiscal Discipline

28. The biggest challenge that we face is the fiscal challenge. The United Front government is committed to bringing the fiscal deficit to below 4% of GDP. This is what the Common Minimum Programme says and this is what I intend to do over a period of time. One plank of the strategy is, of course, to raise more revenues. But without a credible public expenditure management policy, no programme of fiscal deficit reduction will be sustained. I believe that no one is against austerity or efficiency as such. At the same time, I accept the position that sound expenditure management is not a mere technocratic exercise but involves issues of equity, fairness and non-discrimination. In order to work out a reasonable policy in this regard, I propose to appoint a high-level Expenditure Management and Reforms Commission comprising distinguished political leaders, economists and administrators. This Commission will be given four months - and I hope no more-

to submit its recommendations on public expenditure management and control as far as the Central government is concerned. The report will be made public immediately so that we can generate an informed public debate on an issue that has a vital bearing on our economic future.

29. I also propose to place before the House a discussion paper on subsidies. The paper will list all the subsidies, visible and hidden, so that there can be an informed debate and a consensus on the overall level of subsidies as a percentage of GDP and their appropriate targeting.

30. In the meantime, I intend to be strict in matters relating to cash management, project portfolio review, adherence to budgetary ceiling and adequacy of returns from public sector enterprises.

31. Hon'ble Members are aware that in September 1994 an agreement was signed between the Central Government and the RBI to phase out the system of *ad-hoc* treasury bills by 1997-98. The experience last year and in the current year so far has shown the difficulty of staying below the within-year limit. Nevertheless, I remain convinced that the system of *ad-hoc* treasury bills must be phased out. However, before this can happen we need to put in place a better expenditure control mechanism. We also need a more transparent method of defining and reporting the true budget deficit, including all forms of monetisation. I shall present concrete proposals in this regard at the time of presentation of next year's budget so that RBI can have greater autonomy in formulating and implementing monetary policy.

Insurance, Banking and the Capital Market

32. Earlier I made a reference to insurance in the context of long-term finances. LIC and GIC are our two premier institutions in the insurance sector. I intend to strengthen them. The strength of an insurer has to be measured by the range and quality of its services and products and by the number of people availing of those services and products. I am happy to announce that I have been able to persuade LIC and GIC to offer two new services aimed at the middle class and the poor.

33. LIC will offer a new pension scheme called "Jeevan Suraksha". The details of the new scheme will be announced separately but an illustration of how the scheme will work can be given. A person who subscribes to the scheme at age 30 for a period of 30 years by paying just Rs.250 per month will get a life pension of Rs.3,500 per month beginning at age 60. In addition, that person will get 25% of the commuted value of the pension - about Rs.1 lakh - immediately on retirement. If the insured person dies before retirement, the spouse will be paid a substantial life-long pension. This scheme will meet a long-felt need amongst a large number of people for economic security beyond their working life. To launch this personal-cum-family pension scheme, I am proposing some fiscal incentives which I shall outline later.

34. Medical insurance is an area where the quality of the product can be greatly improved. Under the existing Medicare scheme, the maximum cover available is Rs.83,000 which is further segmented into different components. This ceiling is being enhanced to Rs.3 lakh with a single aggregate limit.

35. Furthermore, the GIC will launch a new low price medicare policy appropriate to the vast majority of our people. Jeevan is the brand name for the LIC and we respect intellectual property rights. So we are calling this new scheme "Jan Arogya". The policy will provide a cover upto Rs.5,000 per year with an annual premium of only Rs.70. What is more, a family of four comprising the husband, wife and two children below the age of 25, can pay an annual premium of Rs.240 and get cover for Rs.20,000 for the family as a whole. GIC will soon announce the details of this scheme.

36. I have advised LIC and GIC to introduce modern information technology in their business. I have also asked LIC to review the premium structure based on the latest mortality tables.

37. An interim, non-statutory Insurance Regulatory Authority was set up in January 1996. I now propose to introduce a Bill to make it a statutory body and to empower it suitably. When I return to the subject of insurance in the next Budget, I shall

address some of the policy parameters outlined in the Common Minimum Programme, including the sequence of steps for the restructuring of the insurance industry.

38. Reform of the banking sector has been an integral part of the process of economic reforms. The public sector banks have shown an improvement in profitability and capital adequacy and are taking steps to adopt improved technology. The entry of private sector banks has added a welcome measure of competition. Hon'ble Members are aware that in the past three years the government provided a total of Rs.11,840 crore to recapitalise several public sector banks. I am happy to inform the House that three of these banks are now in a position to return part of the capital, amounting to Rs.747 crore, reflecting an improvement in their performance. This re-flow of resources will help to recapitalise some more public sector banks for which a provision of Rs.909 crore is being made in 1996-97. Some of the strong public sector banks are also planning to recapitalise themselves by accessing the capital markets directly. Hon'ble Members will be pleased to know that the State Bank of India is today a prized scrip in the market. I am also providing Rs.200 crore in 1996-97 for restructuring and recapitalising the Regional Rural Banks.

39. The capital market has a crucial role to play in raising funds for new investment. Government will ensure healthy development of the capital markets through effective regulation, greater transparency and improved trading and settlement practices. Our major stock exchanges have already introduced on line electronic trading. The commencement of a Central Depository, which is expected in the course of this year, will be a historic further step in the modernisation of the capital markets.

40. The present regulations governing foreign institutional investors allow investment only in listed securities. There is also a limit of not more than 5% for an individual FII and an aggregate of 24% for all FIIs in the stock of a listed company. It has been represented that these limits should be liberalised. Besides, FIIs are unable to invest in infrastructure because most infrastructure projects are set up by new companies which are

not expected to be listed for some time. Having regard to these representations, I propose to raise the limit of 5% for an individual FII to 10% subject, however, to the aggregate limit of 24% for all FIIs. I also propose to allow them to invest in unlisted companies in the same manner as they are allowed to invest in listed companies. The revised guidelines are being issued separately by SEBI.

Non Banking Finance Institutions

41. Serious concerns have been expressed from time to time about the activities of a number of non-banking financial institutions, both corporate and non-corporate. I am happy to inform the House that, in consultation with the Reserve Bank of India, we have decided to bring before this House amendments to the RBI Act to strengthen the regulatory powers over all kinds of non-banking financial companies.

Corporate Sector

42. It is widely acknowledged that the Companies Act 1956 needs to be re-written comprehensively. Some work has already been done. I intend to constitute a small drafting team comprising persons with knowledge of law, economics and company affairs to prepare a new draft and make it ready for public debate. My deadline is January 1, 1997.

43. In the meanwhile, I propose to introduce some urgent amendments to the present Act to provide for the following :

- Companies defaulting on payment of interest or repayment of principal on deposits will be debarred from raising further deposits until these defaults are remedied.
- The present ceiling of Rs.1,000 on the claims of arrears of wages and salaries of employees in case of winding up of a company is absurdly low. This will be enhanced.
- Mutual funds and venture capital funds will be permitted to vote in respect of their holdings in companies.
- Non-voting shares will be permitted upto 25% of the issued equity capital. This will go a long way in meeting the demand for a level playing field.

- Companies in the infrastructure sector will be allowed to issue shares that are redeemable after the expiry of a period of 20 years from the date of issue.

44. Hon'ble Members will agree with me that these changes are necessary and should be introduced right away. Next year, I shall come back to the House with a new Companies Bill.

45. In order to achieve competitiveness, Indian industry must be given easy access to improved technology. At present RBI accords automatic approval for technology imports subject to the requirement that royalty will be limited to 5% on domestic sales and 8% on export sales and that the lump sum payment does not exceed Rs.1 crore. All other cases require case-by-case approval by the Central government. Industry has represented that the Rs.1 crore limit for automatic approval needs to be increased. Responding to this demand, it has been decided to increase this limit to \$ 2 million (equivalent to about Rs.7 crore). With this liberalisation, a large number of technology import cases will not have to come to government.

46. The Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) was constituted to function as the principal credit and reconstruction agency. Thanks to rapid changes, the burden of reconstruction is being shared by different stakeholders including development financial institutions and banks. I, therefore, propose to transform the IRBI into a fulfilled, all-purpose development finance institution with headquarters in Calcutta. I will soon bring the necessary changes in the statute governing IRBI.

FIPB, Tariff Commission and Disinvestment Commission

47. In keeping with the promises made in the Common Minimum Programme, government have reconstituted the Foreign Investment Promotion Board. The Foreign Investment Promotion Council will also be set up shortly. Together, they will vigorously promote and approve foreign direct investment in India keeping in view the objective of attracting at least \$ 10 billion every year.

48. In order to expedite foreign investment approvals and also increase the transparency of the process, government have

decided to expand the list of 35 industries which are eligible for automatic approval upto 51% of foreign equity. The expanded list will be announced separately by my colleague, the Minister of Industry. At present, the automatic approval procedure is subject to the requirement that the value of foreign equity should cover the total import of capital goods. This condition was introduced in 1991 when capital goods imports were subject to import licensing. As capital goods have been free of import licensing restrictions since 1992, this condition is being dropped.

49. Government have also initiated action to set up an independent Tariff Commission.

50. Government have approved the proposal to establish a Disinvestment Commission. Any decision to disinvest will be taken and implemented in a transparent manner. Revenues generated from such disinvestment will be utilised for allocations for education and health and for creating a fund to strengthen public sector enterprises. The interim Budget for 1996-97 took credit for Rs.5,000 crore through disinvestment. I propose to take credit for the same amount. The disinvestment will be done in three tranches, approximately in September, November and January/ February.

Industrial Sickness

51. The Sick Industries Companies Act (SICA) has a narrow definition of sickness and cannot deal with incipient or potential sickness. Managements have been able to use the BIFR route to abdicate their legitimate responsibilities. Under the present dispensation workers, financial institutions, banks and government are often the losers. I have initiated a total review of SICA and the working of BIFR and I intend to bring a new Bill in the winter session of Parliament.

Centre-State Relations

52. I have already made a reference to the Chief Ministers' Conference on Basic Minimum Services. The Prime Minister intends to call another conference of Chief Ministers to discuss the political aspects of Centre-State relations and federalism. At the last conference, the Chief Ministers expressed the view that

many centrally-sponsored schemes should be retained as such and should continue to be funded by the Central government. While we respect the views of the Chief Ministers, it is our desire that most Centrally-sponsored schemes should be transferred to the control of the State governments. In the meantime, States will be given greater flexibility in the implementation of these programmes. Provisions available under all other schemes will be pooled and the basic entitlement ratio will be worked out for each State. The States will be free to select for implementation, within their annual entitlement, such schemes that are more suited to their needs. The Ministry of Planning and Programme Implementation is working on the revised guidelines and procedures in consultation with the concerned Ministries and the States.

53. I also intend to circulate a discussion paper to Hon'ble Members on the 10th Finance Commission's recommendation to form a single divisible pool of taxes to be shared between the Centre and the States. Prima-facie, the Finance Commission's recommendation appears to be in the national interest but it will require an amendment to the Constitution. Hence, I wish to encourage a debate before a final decision is taken.

54. The Common Minimum Programme has promised that the Government will, within six months, bring out a detailed document that will articulate the priorities and programmes of the Ninth Plan. While a number of programmes have been initiated in this Budget, it will be our endeavour to prepare an Approach Paper to the Ninth Five Year Plan within four months. The Ninth Plan will target a growth rate of 7% per annum and will articulate strategies for decentralisation of responsibilities, for raising resources and for ensuring widespread growth. The initiatives that have been taken this year will be followed by a more comprehensive programme of social and economic development with the focus on elimination of poverty.

55. I shall now briefly go over the Budget estimates.

56. As Hon'ble Members are aware details of the revised estimates for 1995-96 were presented along with the interim

Budget in February 1996. I am, therefore, not going over those estimates again. The figures that are given below are the budget estimates for 1996-97 and for plan expenditure I shall compare them with the budget estimates for 1995-96.

57. For 1996-97, the total expenditure is estimated at Rs.204,698 crore. Of this, Rs.54,685 crore is gross budgetary support for the Central Plan and assistance to State and UT plans, representing a sharp increase of 13% over Rs.48,500 crore. Non-plan expenditure is placed at Rs.150,013 crore.

58. Central assistance for State and UT plans is being stepped up from Rs.19,506 crore to Rs.21,972 crore. The increase will provide funds to the States for implementing the seven Basic Minimum Services schemes to which I have referred earlier.

59. Gross budgetary support for the Central Plan is being enhanced from Rs.28,994 crore to Rs.32,713 crore.

60. All anti-poverty programmes will be reviewed with a view to strengthening them and providing them with more funds. The plan allocation for the Department of Rural Development has been increased from Rs.1,263 crore to Rs.2,195 crore. The plan allocation for the Department of Rural Employment and Poverty Alleviation is Rs.6,437 crore.

61. The plan allocation for the Department of Fertilizers has been increased from Rs.205 crore to Rs.373 crore in order to increase domestic production.

62. For tapping the potential of non-conventional energy sources, the plan allocation for the Ministry of Non-Conventional Energy is being raised by Rs.87 crore to Rs.334 crore.

63. Mr. Speaker, Sir, I hope Hon'ble Members will forgive the Finance Minister if he is partial to the cause of exports. After all, I cut my teeth in economic administration in the Ministry of Commerce. Promotion of exports must remain high on our agenda. Hence, I propose to provide a sum of Rs.50 crore for the corpus of the recently established India Brand Equity Fund. I would appeal to industry and trade to contribute at least an equal amount in this financial year itself. A sum of Rs.25 crore has been

provided for critical balancing infrastructure. Non-plan provision for export promotion and market development has been enhanced from Rs.315 crore to Rs.460 crore. Deemed exporters will now get refund of terminal excise duty in quick time.

64. The plan allocation for the Department of Health has been stepped up from Rs.647 crore to Rs.792 crore.

65. The plan allocation for the Department of Education has been increased substantially from Rs.1,825 crore to Rs.3,388 crore. This will help in implementation of the District Primary Education Programme and the mid-day meal scheme.

66. This government is committed to safeguard the interests of women and children by expanding the social safety nets. The annual plan allocation for the Department of Women & Child Development is being stepped up from Rs.730 crore to Rs.847 crore. The allocation for the Integrated Child Development Scheme is being increased from Rs.588 crore to Rs.682 crore.

67. The plan allocation for the Ministry of Labour has been increased from Rs.136 crore to Rs.188 crore. Enhanced provisions have been made for schemes relating to improvement in the working conditions and for training of workers.

68. In the Railway Budget presented a few days ago, government have announced an outlay of Rs.8,130 crore in the Railway plan for the current year with a budgetary support of Rs.1,269 crore. Based on the ability of the Railways to meet their stipulated targets on internal resource generation, I will consider increase in the budgetary support during the course of the year for this crucial sector.

69. The plan allocation for the Ministry of Surface Transport has been increased by Rs.240 crore to Rs.1,322 crore, mainly to provide enhanced support for national highways. Schemes are on the anvil to make Kochi and Tuticorin important trans-shipment ports for container traffic.

70. There are persistent demands from the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep for more flexible norms for

determining the cost for funding and implementing projects. Having regard to their special needs, I have agreed to these demands. We will also ensure that the Island Development Authority is activated to accelerate development in these strategic islands.

71. I am happy to inform Hon'ble Members that the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) is being continued in the current year. Adequate funds are being made available for this scheme.

72. The total non-plan expenditure in 1996-97 is placed at Rs.150,013 crore compared to Rs.123,651 crore in BE 1995-96 and Rs.134,320 crore in RE 1995-96. Of the increment, Rs.8,000 crore is on account of increase in interest payments, the provision for which is now placed at Rs.60,000 crore. The provision for Defence expenditure has been increased from Rs.26,879 crore in RE 1995-96 to Rs.27,798 crore. I assure Hon'ble Members that, if required, more funds will be made available in order to equip and keep our armed forces in fighting fit condition.

73. I have already referred to the major new initiatives for giving an impetus to agriculture and irrigation. The increase on account of higher subsidies for phosphatic and potassic fertilisers will be Rs.1,724 crore over last year's provision of Rs.500 crore. The enhanced subsidies are expected to lead to a balanced use of various fertilizers for better soil health and productivity.

74. The provision for food subsidy has also been increased from Rs.5,500 crore to Rs.5,884 crore.

75. A provision of Rs.449 crore has been made for writing off the outstanding interest and conversion of loans into equity in the subsidiaries of Bharat Yantra Nigam Ltd., Bharat Bhari Udyog Ltd. and Hindustan Paper Corporation Ltd. under BIFR approved revival plans. In addition, a provision of Rs.1,270 crore has been made for non-plan loans to public sector enterprises mainly for payment of salaries and wages to the employees.

76. I now turn to the revenue receipts. Gross tax revenues at the existing rates of taxation are estimated at Rs.129,453 crore. After providing Rs.34,451 crore as the share of taxes of the States, the Centre's net tax revenue will be Rs.95,002 crore. Non-tax revenues, an important component of our receipts, have also shown healthy buoyancy. The receipts under this head, which were estimated at Rs.29,103 crore in RE 1995-96, are expected to be Rs.33,035 crore this year. I am confident that we can do better under some heads. I have taken credit for Rs.2,500 crore as license fee from private operators of cellular and basic telecom services.

77. The net revenue receipts for the Centre, including non-tax receipts, are expected to increase from Rs.110,191 crore in RE 1995-96 to Rs.128,037 crore in 1996-97.

78. In the area of capital receipts, traditional market borrowings are placed at Rs.3,700 crore. Other medium and long-term loans are estimated at Rs.21,798 crore. Net external assistance will be Rs.2,461 crore. I am also taking credit for receipts from disinvestment of equity in public sector enterprises of Rs.5,000 crore. Total receipts at the existing rates of taxation are estimated at Rs.195,774 crore while total expenditure is Rs.204,698 crore. I shall come to the Budget deficit and the fiscal deficit in Part B of my speech.

PART B

79. Now, I turn to my tax proposals.

80. The good news is there are no new direct taxes save one and even that solitary new tax, I am confident, will be almost universally welcomed.

81. There are pressing demands from all sections of society to raise the threshold limit for personal income-tax from the existing level of Rs.40,000 to at least Rs.60,000. Each increase of Rs.1,000 in the threshold limit will cost the exchequer Rs.150 crore and, since 77.5% of this loss will be borne by the States, any major concession on this front will put a severe strain on the States' financial resources. Besides, when the direct tax base is already narrow - only 110 lakh persons pay income-tax - no Finance Minister can afford to let 20 or 30 lakhs of them go out of the net. However, I accept the need to provide relief to the assesseees in the first tax bracket, especially the salaried class. I propose to do so in two ways: first, I propose to reduce the income-tax rate for the first bracket from 20 per cent to 15 per cent. This benefit will be available to all assesseees. I also propose to raise the standard deduction from Rs.15,000 to Rs.18,000 for salaried employees having an income upto Rs.60,000. Thus, a salaried employee with an income of Rs.60,000 per year, making the minimum contribution to his provident fund, will now pay no tax at all. If he has no savings, he will still pay only Rs.300.

82. We owe a special consideration to our senior citizens. At present, senior citizens benefit from a special tax rebate of 40% upto an income level of Rs.100,000. I propose to raise this to Rs.120,000.

83. House-owners, residing in their own houses that have been financed by borrowing, deserve relief. The deduction of interest payments of Rs.10,000 allowed to them from their income from property is proposed to be raised to Rs.15,000.

84. As another relief measure, I propose to raise the limit under section 80D of the Income-tax Act for deduction in respect of insurance on the health of the individual and his family members from Rs.6,000 to Rs.10,000.

85. I have already mentioned the new scheme of personal-cum-family pension being introduced by LIC. In order to encourage savings in this form, I propose to allow the contribution to the pension fund to be deducted from taxable income upto a limit of Rs.10,000 per annum. I also propose to exempt the income of such a pension fund in the LIC from the levy of income-tax.

86. At present, a five year tax holiday is available under section 80-IA to enterprises engaged in developing, maintaining and operating infrastructure facilities such as roads, highways, bridges, new airports, ports and rail systems. I propose to extend this incentive to investment in irrigation, water supply, sanitation and sewerage systems.

87. I also propose to provide a five year tax holiday under section 80-IA of the Income Tax Act to companies exclusively created to participate in research and development activities. I am also simplifying the existing procedure for giving weighted deduction under section 35(2AA) of the Income-tax Act on sums paid for scientific research to a National Laboratory or a University or an Indian Institute of Technology by deleting the condition of approval by an outside body.

88. Infrastructure funds have become an important source of capital to finance infrastructure projects. In order to encourage such funds established to mobilise resources for financing infrastructure facilities, I propose to exempt them from income-tax. Any dividend, interest or long-term capital gains of such funds

or companies from investments in the form of shares or long-term finance in any enterprise set up to develop, maintain and operate an infrastructure facility will be free from income tax.

89. I also propose to allow investment in approved debentures or equity shares of public companies as eligible for tax rebate under section 88 if the proceeds of such public issues are applied to create a new infrastructure facility or to generate or distribute power. In the case of such investment, the limit of Rs.60,000 under section 88 will be raised to Rs.70,000.

90. Corporate tax rates have been reduced and simplified over the past few years and the results have been very encouraging with a significant increase in corporate taxes as a percentage of GDP. However, there are two issues which need to be addressed. The first is the promise made in the past that the corporate surcharge will be temporary. The other is the phenomenon of zero tax companies which, according to many observers, reflects an excessive degree of laxity in the tax regime. I propose to respond to the two issues as follows :

- (i) I am reducing the rate of surcharge on corporation tax from 15% to 7.5% and hope to take a similar step in my next budget. The reduced tax burden will benefit all companies big and small.
- (ii) I propose to introduce a 'Minimum Alternate Tax' (MAT) on companies. In a case where the total income of the company, as computed under the Income Tax Act after availing of all eligible deductions, is less than 30 per cent of the book profit, the total income of such a company shall be deemed to be 30 per cent of the book profit and shall be charged to tax accordingly. The effective rate works out to 12 per cent of book profit calculated under the Companies Act. Companies engaged in the power and infrastructure sectors will, however, be exempted from the levy of MAT.

91. As a step towards achieving a level playing field for Indian companies vis-a-vis the foreign companies, I propose to reduce the tax on long-term capital gains in the case of domestic companies from 30 per cent to 20 per cent.

92. In order to encourage savings and to channelise savings into investments in priority sectors of the economy, I propose to exempt from tax long-term capital gains if the net consideration received or accruing from the transfer of the capital asset is invested in specified assets for a period of three years or, alternatively, if the entire capital gains are invested in specified assets for a period of seven years. The assessee will now have a choice of two new savings instruments.

93. I also propose to allow depreciation in the case of fractional ownership of assets because of the need for joint financing of big, capital intensive projects by a consortium of financiers having fractional shares in the assets.

94. In order to promote efficiency in industry, I propose to provide that unabsorbed depreciation will be carried forward for a period of eight years only in the same manner as business losses.

95. The practice of sale-and-lease-back of assets results in passing of very high depreciation to the leasing concerns. This needs to be curbed. Hence, I propose to provide in the Income Tax Act that in case of sale-and-lease-back transactions, the written down value of the asset, in the hands of lessee, who was the previous owner, will be treated as cost in the hands of the lessor. This measure, while not affecting bonafide transactions, will prevent loss-making concerns from indulging in unhealthy trade-off of depreciation.

96. I find it unreasonable that commercial properties, not used by the assessee as his business, office or factory premises, should be outside the levy of wealth-tax. Accordingly, I propose to plug this unintended loophole and levy wealth-tax on such commercial properties.

97. Other measures of tax relief proposed by me include —

- (i) Allowing a special deduction of Rs. 15,000 to the patient or guardian of a patient of protracted diseases like cancer or AIDS involving considerable expenditure on treatment.
- (ii) Exempting under section 10(24) of the Income Tax Act the income of an Association of Registered Trade Unions.

(iii) Extending 100 per cent deduction under section 80G of the Income Tax Act to —

- (a) Donations made to Illness Assistance Funds established by the Central government and the State governments to meet the medical expenses of the poorest of the poor;
- (b) Donations made to State and National Councils of Blood Transfusion recently set up by the Ministry of Health and Family Welfare; and
- (c) Donations made to the three funds established by the armed forces of the country. These are the Army Central Welfare Fund, The Indian Naval Benevolent Fund and the Air Force Central Welfare Fund. This is my way of saluting the brave officers and jawans of our armed forces.

98. As a part of our obligation to SAARC I am exempting from income tax the income of SAARC Fund for Regional Projects (SFRP).

99. In order to promote industrial development in the North-Eastern region of the country, a North-Eastern Development Finance Corporation was established in August, 1995. I propose to exempt its income from tax.

100. These proposals are likely to result in an improvement of revenue under direct taxes which is estimated at Rs.912 crore.

101. I shall now come to the proposals relating to indirect taxes.

102. Over the last few years steps have been taken to reform our indirect tax structure by reducing the number of rates, removing exemptions and by switching over to *ad-valorem* rates. On the customs side the peak rate of duty was reduced to 50% in 1995-96 accompanied by reduction in rates down the line in respect of all commodities. Central excise duties were also revamped and moved closer to a Value Added Tax with the introduction of Modvat for capital goods and extension of input

credit facilities to almost all items necessary for the manufacture of goods. These changes have contributed to the growth in industrial production, simplified the tax structure and brought about greater transparency. They have also led to strong growth in revenues, with indirect tax collections increasing by 19 per cent in each of the last two years, in spite of substantial reduction in rates. The Common Minimum Programme mandates the government to continue with tax reforms and I propose to do so.

103. Keeping in view the twin objectives of making our industry globally competitive and providing it reasonable levels of protection in the transitional period, I propose to take measured and calibrated steps in the matter of customs tariffs.

104. The salient features of my proposals are—

- Reduction in customs duties on crude oil and other basic petrochemical intermediates.
- Reduction in the rates of customs duties on raw materials and inputs such as chemicals, plastics, natural rubber and ferrous and non-ferrous metals.
- Substantial reduction in customs duties on raw materials and components required for giving a thrust to the electronic goods sector.
- Reduction in the rate of duty on computers for giving a boost to the software industry.
- Reduction in import duty on selected machinery to modernize the textiles and garment sector.
- Removal of several anomalies in duty rates.
- Unification of rates on similar items in order to substantially reduce disputes on classification and on rates.
- Retention of only such exemptions which are necessary, for the present.

105. India has become a major producer and exporter of chemicals. This industry has shown a healthy growth in the last

two years. This is an area in which India can exploit its potential of trained technical manpower and become a leading nation of the world in the production of chemicals. To achieve these objectives, I propose to take the following steps:

- Reduction in the rate of duty on crude oil from 35% to 25%.
- Reduction in the rate of duty on bitumen from 30% to 10%.
- Unification of rates at 10% on petro chemical building blocks such as cumene, toluene and cyclohexane.
- Reduction in the rate of duty on chemicals, both organic and inorganic, from 50% to 40%.

106. Our textile industry employs millions of people. It is necessary to modernise it and provide an environment in which it can grow rapidly. I propose the following measures:

- Reduction in the import duty on rayon grade wood pulp from 25% to 5%.
- Reduction in the import duty on acrylonitrile from 20% to 10%.
- Reduction in the rate of duty on DMT, PTA and MEG from 35% to 25%; however in the case of caprolactum the revised duty will be 30%.
- Reduction in the rate of duty on artificial and synthetic fibres from 45% to 30%.
- Unification of the rates of duty on nylon filament yarn, polyester filament yarn and viscose filament yarn from the existing levels of 45% and 40% at 30%.

107. I also propose a major restructuring of excise duties in the textile sector, extending the benefit of Modvat, to which I shall come a little later. I am confident that with these measures our textile industry will grow from strength to strength in the coming years.

108. Our power plants face a shortage of coal on account of

growing demand and better utilisation of installed capacity. I propose to reduce the rate of duty on non-coking coal from 35% to 20%. I also propose reduction of duty on coke from the existing level of 25% to 20%.

109. Our plastics industry is coming of age. I propose a reduction of duty on plastics from 40% to 30%. Further, on articles of plastics I propose a reduction from the existing level of 50% to 40%.

110. In regard to rates of duties on drugs and pharmaceuticals, I propose to retain the zero rate of duty on life saving drugs. I also propose to reduce the rate of duty on all other allopathic medicines from 50% to 40%. In order to make available veterinary drugs commonly used I propose to reduce the rate on specified veterinary drugs from 15% to 10%.

111. There has been a persistent complaint from industry that customs duty on metals is very high and this makes it difficult for downstream industry, especially capital goods, to be competitive. Industry has been demanding that the rate of duty on metals should be brought down drastically. However, realising the need to provide adequate time to our metals industry to adjust itself to global competition, I propose a modest reduction from 35% or 40% at present to a peak rate of 30% on all metals except nickel and aluminium. On unwrought aluminium and unwrought nickel I propose to retain the current level of 10% and 20% respectively. On wrought aluminium I propose to reduce the duty from 25% to 20% and on wrought nickel from 30% to 20%.

112. While I do not wish to tamper with the rate of duty on machinery which stands at 25%, I propose a reduction of duty on signaling and safety equipment for railways, airports, sea ports etc. from the current level of 50% to 25%.

113. The last three years have witnessed a tremendous growth in our electronic industry which has been the result of enterprise as well as the stimulation provided by sharp reduction in customs duties. In order to maintain this trend, I propose the following changes:

- On raw materials, from the existing 15% to 10%

- On components, from 25% to 20%.
- On glass shells for colour TVs, from 30% to 25%.
- On colour picture tubes, from 40% to 30%.
- On computers and computer peripherals, from 40% to 20%.
- Finished goods will continue to attract 50% rate of duty.

114. With a view to encourage sports in the country, I also propose to reduce import duty on sports goods from 50% to 30%.

115. In order to give relief to professional press photographers I propose to allow them to import free of duty photographic equipment upto Rs.1 lakh. A similar concession is also being extended to accredited journalists for import of personal computer, typewriter and fax machine.

116. Telecommunication is a growing sector and will turn out to be the life-line of our economy. The existence of an efficient telecommunication net work is a pre-requisite for accelerated economic growth. In order to give a boost to the efforts being made by the Department of Telecommunications, I propose that the duty on parts and sub-assemblies of telecommunication equipment be reduced from 35% to 30% and on finished equipment from 50% to 40%. In order to avoid the temptation to smuggle cellular phones, pagers and trunking handsets, I propose to reduce the customs duty on them to 30%.

117. Upgradation of medical standards in the country is extremely important. I, therefore, propose to reduce the rate of duty on specified equipment, not generally made in India, and their parts from 15% to 10% and on other medical equipment from 40% to 30%.

118. Edible oils now carry a rate of duty of 30%. This is an important item of daily food for the masses and we have a chronic shortage of edible oils in the country. I propose to reduce the import duty on edible oils from 30% to 20%.

119. Mr. Speaker, Sir, earlier in my speech I dwelt on the dire need to step up investment in infrastructure. I had also detailed the

sectors to which I propose to make large allocations. I have to raise resources to meet these requirements. I intend to ask importers to share the burden of building the infrastructure in this country because, ultimately, it will help raise production and enhance competitiveness. I, therefore, propose a levy of 2% as special customs duty on all imports except those that carry nil rate of duty or are imported at nil rate of customs duty for export production under the various duty free licences. This levy will not apply to gold and silver imported by eligible passengers or under special import licences. This is likely to yield about Rs. 1600 crore in the current year.

120. Importers will be happy to know that the Reserve Bank of India is announcing today the withdrawal of the interest rate surcharge of 25% on import finance imposed in February, 1996.

121. I now come to my proposals regarding central excise. A large number of countries in the world today have a value added tax system which has been recognised to be the most efficient form of commodity taxation. I am glad to note that some State governments are moving towards the value added tax system. The last few years of reforms have taken us closer to having a Central VAT, but there are still certain legal obstacles.

122. Our central excise structure still has 11 ad-valorem rates. The rates range from 0 to 50 per cent. Ideally there should be only four rates of excise duties -- zero, a lower rate of excise duty on goods of mass consumption, a single normal rate on all other goods and a higher rate on luxury items. It is absolutely necessary for us to move towards this rate structure so that we put an end to wasteful litigation and have a transparent and simple tax structure. It was not possible in the time available to me in preparing this Budget to achieve this goal in the current year. However, I propose to take the first step this year and I am confident that we will achieve a four-rate excise duty structure in another year or two.

123. I propose to integrate the tax on the textile sector with the mainstream of central excise duties by introducing the Modvat principle in this sector. Hon'ble Members are aware that at present excise duties are levied at the fibre and yarn stage and there is only

an additional excise duty, in lieu of sales tax, on fabrics. This is one of the most inefficient ways of taxation as it results in very high duties on inputs, which encourages evasion; it does not capture value addition; and it denies the industry an opportunity of claiming Modvat input credit on capital goods, chemicals and yarn. While modernisation of other industries is taking place speedily, our textile industry has not been able to participate fully in this process because of this lopsided tax structure. I, therefore, make the following proposals.

124. I propose to reduce the excise duty on yarn in the case of polyester filament yarn from the current level of 50% to 40% and unify the rates on other yarn at 20%, except nylon filament yarn and cotton yarn for which the present rates of 30% and 5% respectively will be retained. In order to provide Modvat for the textile sector, I propose to impose a basic excise duty of 5% on cotton fabrics and 10% on other fabrics which will be collected at the processed fabric stage. The processors would be in a position to Modvat the duty paid on yarn imputed on the basis that yarn accounts for 50% of the value of the finished fabric. I have adopted a simple procedure of imputed value to avoid the imposition of a basic duty on grey fabrics which are manufactured by thousands of powerlooms. Such powerlooms will, therefore, continue to be outside the excise net. Composite mills and textile processors will be able to avail themselves of Modvat facilities hitherto not extended to them. This restructuring of excise duty, together with the substantial reduction in customs duties on selected machinery and on inputs for the textile sector, should provide a major boost to the textile industry. I believe that this will also simplify the calculation of drawback rates for garment exporters.

125. In my proposals on customs duties, I have proposed a reduction in customs duty on crude oil from 35% to 25%. This is part of a restructuring and rationalisation of the duty structure aimed at encouraging efficient refineries and enabling me to shift the duties from the input stage to the product stage. I propose to make up the loss on customs duty by adjusting the excise duty upward from 10% to 15% on all petroleum products except LPG and kerosene. The proposed changes in customs and excise duties taken together are revenue neutral and will have no impact on the administered prices of petroleum products

126. Honourable Members are aware that almost all articles of mass consumption are already exempt from excise duty and a large number of other widely consumed articles carry a rate of only 10%. I propose to exempt some more articles from excise duty. They are:

- (a) Vanaspathi and margarine,
- (b) Writing and printing paper supplied to all State Text Book Corporations;
- (c) Animal fats and oils;
- (d) Asbestos fibre;
- (e) Metallic ores; and
- (f) Tapioca products.

127. I propose to reduce the duty on the following articles:

- (a) Tooth paste, from 20% to 10%;
- (b) Detergents, from 30% to 25%;
- (c) Cartons, boxes and bags made of paper and paperboard, from 20% to 10%;
- (d) Glassware produced by semi-automatic process, from 20% to 10%;
- (e) Glassware used for table, kitchen etc., from 15% to 10%;
- (f) Articles of asbestos cement, from 25% to 20%; and
- (g) Ceramic articles, other than glazed tiles, from 20% to 15%.

128. I also propose to raise the exemption limit for footwear from Rs. 50 to Rs. 75 per pair.

129. The rates of excise duty on motor vehicles are not in consonance with the accepted classification of such vehicles. I therefore propose the following rationalisation:

- (a) Duty on motor cars and other motor vehicles principally designed to carry not more than six persons, excluding the driver, will remain unchanged at 40%.
- (b) Duty on motor vehicles principally designed to carry more than 6 persons but not more than 12 persons, excluding the driver - 20%
- (c) Duty on other motor vehicles for transport of persons or goods - 15%.

There is no change in the duty on two-wheelers or tractors.

130. If there is one area in which a Finance Minister can both

tax and please, it is cigarettes. Today, however, I shall please you only in a small way by proposing modest increases in the specific duties on cigarettes ranging from about 5% to 7½%. In the case of non-filter cigarettes, not exceeding 60 mm in length, popularly called mini cigarettes, I propose to raise the tax by 25% from Rs.60 per thousand to Rs.75 per thousand.

131. In order to encourage R & D efforts in India I propose to exempt goods developed and patented in India and concurrently in specified countries from the levy of excise duty for a period of three years. I am also rationalising the exemption from customs duty for import of equipment and consumables for R&D institutions.

132. I have proposed the addition of potassium chlorate, copper powder and cigarette lighters to the list of goods eligible for duty exemption under the SSI scheme. The reduction in import duties proposed elsewhere will also substantially benefit the small scale industries. In order to benefit hundreds of small scale manufacturers of matches I have decided to dispense with the physical control system operating on them and introduce the self-removal procedure freeing them from the day to day bother of control. I hope SSI match units will respond with substantial increase in payment of excise duties.

133. I have proposed rationalisation of rates and exemptions both in customs and excise in several other areas. I would not like to take the time of the House by going into these details.

134. Our excise procedures are outdated and not in tune with the times. They need to be modified. They should encourage voluntary compliance with tax laws by the tax payers. With effect from 1st October, 1996, assesseees would no longer be required to furnish copies of invoices along with the monthly returns. All that they would be required to furnish to the excise department will be a simple Return indicating the duty paid on self- assessment basis. Wherever possible the assesseees' computers could also be linked to the Department's computers for on line assessment.

135. I also propose to introduce a scheme of selective audit by the excise officers and dispense with the existing scheme of routine examination and checking of returns and documents furnished by the assesseees. This scheme would also come into force from 1st October, 1996.

136. I am sure that these changes would be widely welcomed by the manufacturers who are required to pay excise duties and I expect them to comply with the laws faithfully. However, I wish to affirm government's resolve to deal with tax evaders sternly. I am proposing suitable changes in the Customs and Excise Acts to provide for mandatory penalty, together with interest, for evasion of duties on account of fraud, collusion, mis-statement or suppression of facts. Henceforth, the mandatory penalty for evasion of duty on these counts shall be equal to the amount of duty evaded. Tax evaders would also be required to pay interest starting from the first day of the succeeding month in which the duty evaded ought to have been paid and also face criminal prosecution.

137. Mr. Speaker, Sir, the Central Excise and Salt Act, 1944, reminds us of the colonial era when excise duty was collected on salt. There is no excise duty on salt and hence the reference to salt is outdated. I propose to delete all references to salt.

138. The Modvat scheme which provides for duty credit on inputs and capital goods has been liberalised considerably over the past few years. Still, there are problems about the coverage of certain inputs and capital goods. I propose to clarify the scope of eligible capital goods by specifying the heading and sub-headings of the tariff relating to capital goods in the Modvat Rules. It is also a matter of concern that there is misuse of the Modvat credit scheme. At present, Modvat invoices can be issued by any dealer registered with the excise department and this facility is reportedly being misused. Therefore, I propose to restrict the issue of Modvatable invoices by dealers upto two stages. Suitable provisions are also being made in the Modvat Rules for charging of interest in the case of wrong availment of Modvat credit and for mandatory penalty for misuse of Modvat facility.

139. The tax on services has come to stay. With a view to widening the tax base, I propose to bring in advertising services, radio paging services and courier services under the tax net. The tax on these services will be at the rate of 5%. While this measure is expected to yield Rs. 150 crore in a full year, I am taking credit only of Rs. 70 crore in the current year.

140. My proposals relating to reduction in customs duties are estimated to result in a loss of Rs.650 crore in the remaining part of the current financial year. However, by taking into account receipts from the special customs duty estimated to be Rs.1600 crore, there will be a net gain of Rs.950 crore in customs revenue.

141. In the case of excise duties, including additional excise duties, a gain of Rs.760 crore is estimated. Of this, the States are likely to get Rs.384 crore as their share of excise duties.

142. I now have something to say on behalf of my colleague, the Minister of Communications. Postal rates, some of which were last revised in 1990, do not meet even the direct cost of most of the services resulting in increasing budgetary support. Notwithstanding this, no change in the rates of ordinary postcard, letter, parcels and other postal services is being proposed. A modest increase is proposed only in respect of two services which are used for business and commercial purposes. The rate of the printed post card is being increased from 60p. to Re.1 and the registration fee is being increased from Rs. 6 to Rs. 8. It has also been decided to introduce a new category of postcard, called Competition Postcard, which alone may be used for responding to any competition organised on or through television, radio, newspapers or magazines. It is proposed to remove the unintended subsidisation by fixing the tariff for this category of postcard at Rs.2. The changes will take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed. The revisions proposed are estimated to yield a modest revenue of Rs.38 crore in 1996-97, still leaving a large postal deficit.

143. Copies of notifications giving effect to the above changes in customs and excise duties will be laid on the Table of the House in due course.

144. My budget proposals have many implications both for the expenditure side and the revenue side. However, Hon'ble Members will be pleased to know that the end result is satisfactory. The revenue deficit in 1996-97 is placed at Rs.31,475 crore or 2.5% of GDP which is significantly lower than Rs.33,331 crore in RE 1995-96 or 3% of GDP. The fiscal deficit comes to Rs.62,266 crore

in 1996-97, which is lower than the figure of Rs.64,010 crore in RE 1995-96. As a percentage of GDP, the fiscal deficit is 5% in 1996-97 compared to 5.9% in the previous year. I hope to do better in my next budget and move along the path of reducing the fiscal deficit to below 4%.

145. Mr. Speaker, Sir, at the end of this exercise, I ask myself what is a budget about? While it is a measure of the health of the economy, it is also a mirror to the travails and aspirations of the people. 2000 years ago, Saint Tiruvalluvar laid down the golden rule for the King's Ministers:

"Iyattralum, eettalum, kattalum, katta
Vakuthalam Vallath Arasu"

(To be able to increase wealth, to lay it up and guard,
And also well to distribute it, marks a royal lord.)

146. I have made an attempt to raise revenues without putting any burden upon the poor, to allocate large resources for agriculture, irrigation, infrastructure and the social sector, to provide more funds for basic minimum services, to give tax reliefs to the salaried and the middle classes and to promote savings and investment. I have strived to serve the seven objectives that I declared at the outset.

147. The Common Minimum Programme is absolutely right when it says that the country's GDP needs to grow at over 7% per year in the next 10 years in order to abolish poverty and unemployment.

148. I believe that our economy is on a high growth curve. Wisdom dictates that we remain on that curve. In order to do so, we need more reforms, not less. We need more resources, not less. We need more discipline, not less. And we need more compassion, not less. If we remain true to the Common Minimum Programme, we shall overcome our difficulties and take India to the frontline of the nations of the world. This budget, my maiden effort, attempts to blend—I hope in the right proportions—courage and compassion, reform and restraint and growth and social justice.

149. Mr. Speaker, Sir, with these words, I commend this budget to this august House.

C. M. VASUDEV, Addl. Secy. (Budget)

